राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 231 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शनिवार ,13 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए, दामाद के लिए: सीतारमण

नई दिल्ली, (संवाददाता)। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष की किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बुधवार और गुरुवार को कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखा। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2021 पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब देंगी। कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की उम्मीदों के बीच, सीतारमण ने एक फरवरी को बजट पेश किया था। आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है इसलिए राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत होगी। वहीं टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा, पीएम आवास योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। क्या यह अमीर के लिए हैं 17 अक्तूबर से पीएम सौभाग्य योजना के तहत 2.67 से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया। सरकार के ई-मार्केट पर रखे गए ऑर्डर का कुल मूल्य 8,22,077 करोड़ रुपये है। क्या उन्हें बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है उन्हें एमएसएमई को दिया जा रहा है। सीतारमण ने कहा, विपक्ष में कुछ लोगों की यह लगातार आदत बन गई है वह हमारे ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसके बावजूद हम गरीबों काम कर रहे हैं और इस देश के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कदम उठाए रहे हैं। आरोप लगाने के लिए झूठे आख्यान बनाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, 80,00,00,000 लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, 8,00,00,000 लोगों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराई गई और 40,00,00,000 लोगों, किसानों, महिलाओं, दिव्यांग और गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, यह एक ऐसा बजट है जो स्पष्ट रूप से अनुभव, प्रशासनिक क्षमताओं और पीएम के अपने लंबे निर्वाचित कार्यकाल के दौरान का एक्सपोजर है- इस देश के सीएम और पीएम के तौर पर उन्हें विकास, प्रगति और सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।

टीएमसी छोड़कर सुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, तापसी मंडल, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, अशोक डिंडा, दीपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, शीलभद्र दत्ता, श्यांपदा मुखर्जी, बनश्री मैती, बिस्वजीत कुंडू, प्रबीर घोषाल, वैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष और पार्थसारथी चटोपाध्याय भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा, पार्टी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। कांग्रेस सांसद के के सुरेश और टीएन प्रतापन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद रितेश पांडे ने लोकसभा में भारत के सभी हिस्सों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के विस्थापन पर चर्चा की मांग की।

राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यह बजट नए भारत, एक मजबूत भारत के निर्माण और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दशार्ता है। यह हमें एक आर्थिक और विनिर्माण बिजलीघर बनने के मार्ग पर स्थापित करेगा। मैं कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को यह दिखाने के लिए चुनौती देता हूं कि यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली समाप्त हो जाएगी। हम भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, सांसद दिनेश त्रिवेदी ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और घुटन का हवाला देते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की, हालांकि आसन की तरफ से उनकी इस पेशकश को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए उन्हें समुचित तरीका अपना पड़ेगा। उच्च सदन में बजट चर्चा के दौरान आसन की अनुमति से त्रिवेदी ने कहा हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है, जब उसे अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। मेरे जीवन में भी यह घड़ी आ गई है।

उन्होंने कहा मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं देश के लिए आते हैं, देश सर्वोपरि होता है। त्रिवेदी ने कहा कि जब वह रेल मंत्री थे तब भी उनके जीवन में ऐसी घड़ी आई थी जिसमें यह तय करना पड़ा था कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है या खुद मैं बड़ा हूं। तृणमूल सदस्य ने कहा जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, हमारे प्रांत में मुझे यहां बैठे-बैठे लग रहा है कि मैं करूं क्या हम उस राज्य से आते हैं जहां से रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, खुदीराम आते हैं।

उन्होंने उच्च सदन में इसी सप्ताह नेता प्रतिपक्ष के विदाई भाषण के दौरान आजाद और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक हो जाने के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं और कुछ नहीं। मुझसे देखा नहीं जा रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। एक पार्टी से बंधा हूं। मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उसने मुझे यहां (राज्यसभा में) भेजा। त्रिवेदी ने कहा मगर अब मुझे घुटन हो रही है। उधर अत्याचार हो रहे हैं मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज यह कह रही है कि यदि आप यहां बैठकर चुपचाप रहो इसके बजाय यहां से त्यागपत्र देकर बंगाल चले जाओ और लोगों के साथ काम करने का प्रयास करो।

उन्होंने कहा मैं आज यहां से त्यागपत्र दे रहा हूं तथा देश एवं बंगाल के लिए जिस प्रकार काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इस पर उपसभापति हरिवंश ने त्रिवेदी से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें एक समुचित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उन्हें इस बारे में सभापति से बात करनी चाहिए। त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में तीन अप्रैल 2020 को उच्च सदन के सदस्य बने थे और उनका वर्तमान कार्यकाल दो अप्रैल 2026 तक है। संप्रग शासनकाल में त्रिवेदी रेलमंत्री थे और उन्होंने 2012 में रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

भारत लगभग 338 करोड़ रुपये की कोरोना वैक्सीन का निर्यात कर चुका है, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली । भारत लगभग 338 करोड़ रुपये की कोरोना वैक्सीन का निर्यात आठ फरवरी तक कर चुका है। राज्यसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसमें मित्र देशों को मुफ्त में वैक्सीन की खुराक मुहैया करना और कमर्शियल शिपमेंट शामिल है। गोयल ने सदन में पूरक सवालों के जवाब में कहा कि वैक्सीन का निर्यात जनवरी में शुरू हुआ था। भारत पहले घरेलू वैक्सीन की आवश्यकता का ध्यान रख रहा है और उसके आधार पर %मित्र देशों% को टीके दे रहा है।

गोयल ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशिल्ड वैक्सीन का निर्यात भारत सरकार लगभग 125.4 करोड़ रुपये की 62.7 लाख खुराक (फ्री ऑन बोर्ड) अनुदान में दे चुकी है। 1.05 करोड़ खुराक के भुगतान का मूल्य लगभग 213.32 करोड़ रुपये रहा। गोयल ने कहा कि सरकार ने कोरोना के टीकों के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को अनुमति दी है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आगे बताया कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोरोना टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों और वैक्सीन निर्माताओं के बीच नियमित बातचीत के माध्यम से समन्वय बनाया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं।

तमिलनाडुः पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 16 की मौत, सरकार ने किया मुआवजे का एलान

चेन्नई । तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में सत्तूर के निकट पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कम-से-कम 16 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 33 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि अचानकुलम गांव में स्थित फैक्ट्री में यह विस्फोट उस समय हुआ जब पटाखा बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया है। मोदी ने मृतकों के स्वजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख की मदद का एलान किया है। पलानीस्वामी ने भी मृतकों के स्वजनों को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से तीन लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है। पलानीस्वामी ने घटना की जांच का आदेश देते हुए आश्वासन दिया कि मामले में उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्फोट के चलते फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा- तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना दुखद है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी घायल हुए हैं वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस घटना से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन काम कर रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों की मदद की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, तमिलनाडु के विरुधनगर में पटाखा पीड़ितों के परिवार के प्रति दिल से सांत्वना व्क्त करता हूं। जो लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं उसके बारे में सोचना हृदय विदारक है। मैं राज्य सरकार से यह अपली करता हूं कि तुरंत बचाव, मदद और राहत मुहैया कराएं।

राहुल गांधी के दावे को रक्षा मंत्रालय ने बताया बेबुनियाद, कहा- देश के किसी भी क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपा गया

नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर किए गए दावे को रक्षा मंत्रालय ने बेबुनिया बताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चीन के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप किसी भी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा है। और यह कहना कि पैंगोंग सो इलाके में भारतीय भूभाग फिंगर 4 तक है, सरासर गलत है। बता दें कि राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रा राजनाथ सिंह की ओर से संसद की दोनों सदनों में दिए बयान के बाद शुक्रवार को दावा किया कि पीएम मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है। जिस पर अब रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर राहुल गांधी के दावे को बेबुनियाद बताया है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यहां तक कि भारत की धारणा के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर आठ पर है, ना कि फिंगर चार पर। भारत चीन के साथ मौजूदा सहमति समेत फिंगर 8 तक गश्त करने के अपने अधिकार का निरंतर इस्तेमाल करता रहा है। भारत सरकार ने यह भी दावा किया कि पैंगोग सो के उत्तरी किनारे पर दोनों तरफ की स्थायी चौकियां टिकाऊ और बखूबी स्थापित है। रक्षा मंत्रायल ने साफ कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपा गया, बल्कि एलएसी का सम्मान किए जाने को लागू किया गया और एकतरफा तरीके से यथास्थिति में किसी भी बदलाव को रोका है।

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें स्पष्ट करने की जरुरत है। पहली बात यह है कि इस गतिरोध के शुरुआत से ही भारत का यह रुख रहा है कि अप्रै , 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए। राहुल गांधी ने दावा किया, सरकार अपने पुराने रुख को भूल गई। चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन थी, चीन को सौंप दी है। उन्होंने कहा, देपसांग के इलाके में चीन अंदर आया है। रक्षा मंत्री इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। गोगरा और हॉट स्प्रिंग के बारे में एक शब्द नहीं बोला, जहां चीनी बैठे हुए हैं।

भारत का युवा समर्पण से काम करने के लिए जाना जाता है : प्रधान

नई दिल्ली, (संवाददाता)। केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आत्मनिर्भर बजट में जिस तरह से युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया गया है, उससे एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में मदद मिलेगी। इसमें आधारभूत ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। किसी भी देश में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है तो तेजी से बढ़ता है। भारत का युवा अपने काम करने के समर्पण और इच्छाशक्ति के लिए जाना जाता है। दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आत्मनिर्भर बजट पर परिचर्चा के लिए आयोजित युवा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर बजट भारत के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, मीडिया प्रमुख नवीन कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश युवा विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है। उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में किए जाने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले बने मंदिरों में जिस तरह की निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वह आज भी अनूठी है। इस तकनीक के जानकार कारीगर भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित थे।

उन्होंने युवाओं को सलाह दी, कि इस आत्मनिर्भर बजट के बारे में हमें आस-पास के लोगों को बताना चाहिए। इसका एक व्यापक प्रभाव देश के सभी वर्गों के ऊपर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां की जगह जान बचाने को तवज्जों दी और आज हमारा देश काफी तेजी से कोविड फ्री भारत बनने की तरफ अग्रसर है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के इंफ्रांस्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 7,700 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवंटित किया गया है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा मेट्रो फेज-4 परियोजना के चालू होने की बात हो, तीसरे रिंग रोड की बात हो या फिर सिवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात हो, इन सब से सिर्फ दिल्ली में ही युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विश्व का सबसे बड़ा ईको पार्क दिल्ली के बदरपुर में 885 एकड़ जमीन पर बनया जा रहा है और द्वारका के अंदर भारत वंदन पार्क बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। यही नहीं अन्नपूर्णा योजना के तहत कोरोना काल में दिल्ली के लगभग 75 लाख परिवार को मुफ्त राशन देने का भी काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। यह आत्मनिर्भर बजट युवाओं के लिए एक अवसर लेकर आया है। आदेश गुप्ता ने कहा कररहित बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि विपक्ष के पास भी इस आत्मनिर्भर बजट के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति निवास में मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए।

म्यांमार सेना ने भारत से मांगी मदद, इन 40 परिवारों पर खतरा, अलर्ट पर मिजोरम

म्यांमार । पड़ोसी देश म्यांमार में एक दशक से भी ज्यादा वक्त में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही यहा तख्तापलट कर दिया गया है। इसे देखते हुए सशस्त्र उग्रवादी समूह चिन नेशनल आर्मी (सीएनए) ने भारत में अपने परिवारों के लिए शरण की गुहार लगाई है।

परिवारों के लिए शरण का अनुरोध

मिजोरम के चंफाई जिला उपायुक्त मारिया सीटी जुआली ने

जानकारी दी है कि चिन नेशनल फ्रंट (सीएनएफ) की सशस्त्र इकाई सीएनए ने 40 परिवारों के लिए शरण का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा सीएनए ने फरकावन ग्राम परिषद के अध्यक्ष से इस बारे में बात की और उन्होंने चंफाई जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है। जुआली ने आगे बताया कि उन्होंने शीर्ष अधिकारियों को मामले की सूचना दी है ।

बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने की आशंका

वही इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने तख्तापलट के मद्देनजर म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने की आशंका को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। मिजोरम में म्यांमार से लगी 404 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जुआली द्वारा जारी एक अधिसूचना में सभी गांवों को इलाके में म्यांमार के शरणार्थियों के दिखने पर जिला प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

हजारों की संख्या में रह रहे लोग

अधिकारियों ने आगे बताया कि 1980 के दशक में सैन्य जुंटा के कारण म्यांमार के चिन समुदाय के हजारों सदस्य मिजोरम आ गए थे। कई लोग पड़ोसी देश में लोकतंत्र बहाल होने पर लौट गए थे तो वही हजारों लोग अब भी राज्य में रह रहे हैं। आपको बता दें, कि बीते दिनों म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आंग सान सू ची की सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर सेना ने कब्ज़ा कर लिया। जिसे नाराज़ होकर लोग बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

24 घंटों में दुनिया के कई देशों में तेज भूकंप के झटकों को महससू किया गया

इंडोनेशियन । 24 घंटों में दुनिया के कई देशों में तेज भूकंप के झटकों को महससू किया गया, जहां बीते दिन प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी आने का खतरा बढ़ गया और कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया, तो वहीं पश्चिमी इंडोनेशियन में 6.2 आया। इसके अलावा आज अफगानिस्तान में 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटकों से धरती कांपी। साथ ही भारत में मिजोरम में रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता

का भूकंप दर्ज किया गया।

दरअसल, अफगानिस्तान में आज सुबह धरती कांपने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, देश के हिंदू कुश क्षेत्र में गुरुवार को तड़के 4 बजे सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मांपी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, सुबह-सुबग आए भूकंप से लोगों की नींद खुल गई और वे सकते में आ गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है।

वहीं आज ही भारत के मिजोरम में भी भूकंप आया। मिजोरम के चंफाई में रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि झटके से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। हालांकि भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

इसके पहले पश्चिमी इंडोनेशिया के जकार्ता में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं न्यूजीलैंड के उत्तर में समुद्र के नीचे 7.7 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इतनी तेज भूकंप को लेकर सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ब्यूरो के मुताबिक, दक्षणि प्रशांत महासागर में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता के भूकंप को दर्ज किया गया है। इसके बाद सुनामी आ गयी। भूकंप और सुनामी से लॉर्ड होवे द्वीप खतरे में हैं। बता दें कि ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से लगभग 550 किलोमीटर (340 मील) पूर्व में है। इसके अलावा लॉयल्टी द्वीप समूह के पास भी 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है।

पूर्व पीएम प्रचंड बोले- यहां लोकतंत्र खतरे में; डेमोक्रेसी वाले बड़े मुल्क हमारी मदद करें

काठमांडू। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के मुताबिक उनके देश में लोकतंत्र खतरे में है और इस वक्त उन देशों को मदद के लिए सामने आना चाहिए जहां डेमोक्रेसी है और जो इसमें भरोसा रखते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के करीबी माने जाते हैं। दो महीने पहले उन्होंने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद चीन यहां लगातार दखलंदाजी के जरिए अपने हितों को साधने वाली सरकार बनवाने की कोशिश कर रहा है। दहल का बयान एक तरफ जहां चीन की तरफ नाखुशी का इशारा है तो भारत और अमेरिका से मदद की गुहार माना जा सकता है। काठमांडू में विरोधी गुट की रैली को संबोधित करते हुए प्रचंड ने कहा- नेपाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम दुनिया से मदद की अपील करते हैं, खास तौर पर उन देशों से जो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। इन देशों को हमारे प्रधानमंत्री ओली की कदमों का विरोध करना चाहिए। नेपाल में इस वक्त कार्यवाहक सरकार है। कम्युनिस्ट पार्टी ने ओली को प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे पार्टी में वे अकेले पड़ गए। फिर संसद भंग कर दी। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वे चीन के जरिए विरोधियों पर दबाव डालकर फिर सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए देश में उनका विरोध बढ़ता जा रहा है।

भारत ने पहले प्रतिक्रिया दी थी: भारत ने नेपाल में संसद भंग होने के बाद 24 दिसंबर को

प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था- हम नेपाल के हालात पर नजर रख रहे हैं। वहां के लोगों के मदद की जाएगी।

भारत के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने भी लोकतंत्र बनाए रखने की मांग की। लेकिन, चीन इस मुद्दे पर चुप रहा। अब दहल का ताजा बयान चीन की तरफ सीधा इशारा है कि वो नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार को महत्व दे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कर दिया था कि नेपाल में हालात बिगड़ने के पहले ही संभालने होंगे। यूरोपीय देश भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

नेपाल में संसद भंग करने के ओली के फैसले को 13 याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन सभी पर सुनवाई जारी है। अमेरिका ने पिछले दिनों इनका जिक्र किया था। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा था- नेपाल का सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों पर सुनवाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि जनता की मांग पर ध्यान दिया जाए।

ओली के दौर में नेपाल सरकार ने सीधे तौर पर कई ऐसे फैसले किए जो चीन को मदद पहुंचाने वाले हैं। काठमांडू में चीन की एम्बेसेडर तो लगातार और बिना रोकटोक ओली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलती रहीं। सरकार गिरी तो चीनी नेताओं का एक दल काठमांडू भेजा गया। विपक्षी नेताओं को मनाने और उन पर दबाव डालने की कोशिश हुई। लेकिन, अब विपक्षी नेता खुलकर ओली के विरोध में आ गए हैं। ओली का जाना चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। उन पर रिश्वत लेने के भी आरोप हैं।

शुरुआत में ही खटास: बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की

हॉन्गकॉन्ग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के 22 दिन बाद जो बाइडेन ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हालांकि, यह मुलाकात कैसी रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है बाइडेन ने हॉन्गकॉन्ग में मानवाधिकार का मुद्दा उठा दिया। चीन इस मुद्दे को लेकर पहले ही अमेरिका से कई बार भिड़ चुका है। अमेरिका हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र बहाली और वहां के लोगों को मानवाधिकार मुहैया कराने की मांग करता रहा है। चीन ने वहां सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। पिछले साल इसके लिए नया कानून भी बनाया था।

टकराव के मुद्दों पर बातचीत

खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और जिनपिंग के बीच पहली बातचीत में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के आपसी सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडेन ने हॉन्गकॉन्ग में चीन के अड़ियल रवैये पर चिंता जाहिर की और वहां हालात सुधारने पर जोर दिया। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर शिनजियांग प्रांत में उईगर मुस्लिमों को प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा भी उठा दिया। हाल ही में BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए वहां के हालात पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें उईगर समुदाय की महिलाओं के साथ होने वाले

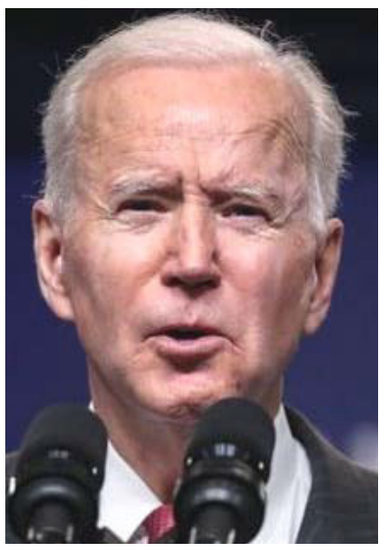

जुल्म को बयां किया गया था।

ये दुनिया का मामला

व्हाइट हाउस के एक सीनियर अफसर ने कहा- प्रेसिडेंट ने जिनपिंग से कहा कि मानवाधिकारों का मसला सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी चिंता की बात है। हम इस पर सख्ती से काम करते रहेंगे। उन्होंने जिनपिंग को यह भी बता दिया कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। हिंद महासागर में मौजूद देशों के हितों की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जाएगी। चीन की आर्थिक नीतियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

बाइडेन का रुख सख्त ही रहेगा

इस अफसर ने कहा- कैम्पेन के दौरान ही यह तय हो गया था कि अमेरिका में आने वाली नई सरकार चीन को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उसकी आर्थिक नीतियां पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं और हम इन्हें सहन नहीं कर सकते। अमेरिका और दुनियाभर में मौजूद चीनी कंपनियों को नियमों के मुताबिक ही चलना होगा। दक्षिण चीन सागर में चीन छोटे देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसके मंसूबों का जवाब देने की तैयारी काफी पहले कर चुका है।

हम अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन चीन ने अगर हिमाकत की तो यह उसके लिए ही परेशानी पैदा करेगा।

चार ड्रोन से आभा एयरपोर्ट पर हमला

यमन। सऊदी अरब में बड़ा हमला हुआ है। सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। ड्रोन से किए हमले में नागरिक विमान में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक, सऊदी अरब के आभा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमला हुआ। विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है। यह एयरपोर्ट यमन की सीमा के काफी पास स्थित है। हूती विद्रोही अक्सर इस एयरपोर्ट पर हमला करते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने लिया है और इसे सैन्य हमला

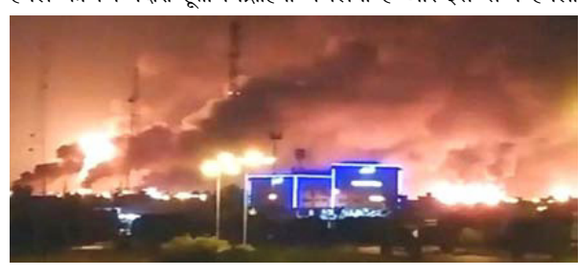

बताया है। सऊदी अरब के सरकार मीडिया ने कहा कि हूती लड़ाकों की ओर से सऊदी अरब के आभा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में डर से भरा हुआ एक आपराधिक आतंकी हमला है। मीडिया ने यह विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे रियाध की अगुवाई वाले सैन्य संगठन के हवाले से कहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने चार ड्रोन से आभा एयरपोर्ट पर हमला बोला है। बता दें कि उत्तरी यमन का अधिकतर इलाका हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। हूती विद्रोहियों की सशस्त्र विंग के प्रवक्ता याहिया सेरी ने दावा है कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल यमन पर हमला करने के लिए हो रहा था। सैन्य संगठन ने इस हमले को युद्ध अपराध बताया है। आगे कहा कि इससे निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। सऊदी नीत सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मलिकी का कहना है कि गठबंधन बलों ने हूतियों द्वारा सउदी अरब की तरफ भेजे गये बम लदे दो ड्रोन विमानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले की निंदा की। उन्होंने इसे सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र में आम आदमी को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है।

आतंकी हमले में चार घायल

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार विस्फोट हुआ है। सुबह हुए इन दो विस्फोटों में चार लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में सामने आई जानकारी के अनुसार, Qowai Markaz क्षेत्र में श्रम मंत्रालय के एक वाहन पर विस्फोट की घटना को अंजाम दिया गया। इस विस्फोट में 4 लोग घायल हो गए। जबकि दूसरा धमाका पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाते हुए किया गया है। यह काबुल में बाराकी गोल

चक्कर के नजदीक हुआ है।

राजधानी में हुए एक ट्वीट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 'काबुल में सुबह एक घंटे से भी कम समय में 2 विस्फोट हुए। सूत्रों से सामने आई खबर में कहा कि कवई मरकज क्षेत्र में श्रम मंत्रालय के एक वाहन में विस्फोट हो गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। एक अन्य विस्फोट ने बाराकी गोल चक्कर में एक पुलिस वाहन को निशाना बनाया।' हालाकिं इन धमाकों को लेकर अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले दिनों कई बम विस्फोट की घटना सामने आ चुकी है।

वहीं इससे पहले 7 फरवरी को सामने आई घटना में दो लोग घायल हो गए थे। इन हमलावरों ने काबुल पुलिस के वाहन को विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया। हालाकिं इस हमले में भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। अफगानिस्तान में लगातार आए दिन हमले-विस्फोट होते रहते हैं। मातम से घिरे इस देश में लोगों का रहना दुस्वार हो गया है।

म्यांमार में मिलिट्री रूल पर बाइडेन सख्त

यूएस में डिपॉजिट एक अरब डॉलर फ्रीज किए गए, म्यांमार के जनरल इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब म्यांमार सेना के आला अफसर एक अरब डॉलर के उस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो अमेरिकी बैंकों में डिपॉजिट है। बाइडेन के मुताबिक, पहले दौर के प्रतिबंध इसी हफ्ते लागू हो जाएंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उन्होंने म्यांमार आर्मी से राष्ट्रपति यू विन मिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की सहित हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को फौरन रिहा करने की मांग की।

बाइडेन प्रशासन अमेरिका में म्यांमार सरकार की तमाम प्रॉपर्टीज को भी फ्रीज करने जा राह है। हालांकि, हेल्थ और सोशल जस्टिस के लिए काम करने वाली ऑर्गनाइजेशन इस दायरे में नहीं आएंगे। बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों पर ताकत के इस्तेमाल का विरोध किया। कहा- हम हर हाल में लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खड़े हैं। अगर म्यांमार का सैन्य शासन वहां सुधार और लोकतंत्र बहाल नहीं करता तो कई तरह के बैन और लगाए जा सकते हैं। बाइडेन ने कहा- म्यांमार के हालात सुधारने के लिए दुनिया को साथ आना होगा, अमेरिका वहां की जनता के साथ खड़ा है।

म्यांमार की सेना ने कहा- इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव होंगे

दूसरी तरफ, म्यांमार की सेना ने कहा कि देश में 1 साल की इमरजेंसी खत्म होने के बाद

चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन में सुधार किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में होने वाले चुनावों की समीक्षा भी की जाएगी। सेना ने कहा कि 8 नवंबर, 2020 को चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटिंग फ्रॉड हुआ। पिछले साल 8 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83फीसदी सीटें जीत ली थीं। चुनाव आयोग ने चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया था।

2011 तक देश में सेना का शासन रहा

म्यांमार में 2011 तक सेना का शासन रहा है। आंग सान सू की ने कई साल तक देश में लोकतंत्र लाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्हें लंबे वक्त तक घर में नजरबंद रहना पड़ा। लोकतंत्र आने के बाद संसद में सेना के प्रतिनिधियों के लिए तय कोटा रखा गया। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि सू की कभी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकतीं।

तख्तापलट का भारत पर असर

म्यांमार में लगभग 50 साल रही फौजी सरकार भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के पक्ष में नहीं रही। हालांकि, भारत म्यांमार में लोकतंत्र का सपोर्ट करता है। इसलिए म्यांमार की सेना के चीन की ओर झुकाव का अंदेशा है। ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि चीन म्यांमार के विद्रोहियों को हथियार देकर उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहा है। ऐसा करके यह पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाना चाहता है। नीदरलैंड के एमस्टर्डम आधारित थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था।

यूएई की सबसे बड़ी अंतरिक्ष उड़ान: 7 माह में 49.4 करोड़ किमी की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंचा 'होप'

अबुधाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का पहला मानवरहित मंगल मिशन 'होप प्रोब' 7 महीने बाद 49.4 करोड़ किमी की यात्रा कर मंगल की कक्षा में पहुंच गया। मिशन के सफल होते ही यूएई ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। जैसे- उसने पहली कोशिश में अपना अंतरिक्षयान मंगल की कक्षा तक पहुंचा दिया। पहला मुस्लिम देश बना, जिसका मार्स मिशन सफल रहा।

मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश भी बन गया। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत ही मंगल की कक्षा तक पहुंच सके हैं। यूएई की स्पेस एजेंसी के मुताबिक, होप यान 1.20 लाख किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है।

लक्ष्य- मंगल का पहला ग्लोबल वेदर मैप तैयार करना

होप का लक्ष्य मंगल का पहला ग्लोबल वेदर मैप भी तैयार करना है। यह मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह मंगल के हर हिस्से पर नजर रखेगा।

खतरा- मंगल से दूर निकलने और नष्ट होने की संभावना

यूएई के वैज्ञानिकों ने बताया कि होप की रफ्तार तेज की तो वह मंगल से दूर निकल जाएगा। यदि होप धीमे जाता है, तो वह मंगल पर नष्ट हो सकता है।

चीन का तियानमेन-1 और 18 फरवरी को अमेरिका का अंतरिक्षयान मार्स पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक माह में तीन अंतरिक्ष यान का मंगल पर पहुंचना अप्रत्याशित है।

10 दिन के भीतर अमेरिका और चीन के यान भी पहुंच जाएंगे

मंगल पर पहुंचने का लक्ष्य 90 दिन का था, लेकिन तकनीकी कारणों से लेट पहुंच रहा है।

यह मंगल के पानी, मिट्टी, चट्टानों और पर्यावरण का अध्ययन करेगा। तस्वीरें लेगा। चार्ट और मैप भी बनाएगा।

अमेरिका का प्रिजर्वेंस रोवर, नासा का पांचवां व्हीकल

30 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 18 फरवरी को पहुंचेगा।

687 दिन (मार्स के साल के मुताबिक) में मंगल पर पहुंचने का था। समय पर पहुंचने के आसार हैं।

भूगर्भ और मंगल पर जीवन की संभावनाएं खोजेगा। सतह के नमूने जुटाकर वापस धरती पर लौटेगा।

61 साल में 58 मिशन; सबसे ज्यादा 29 अमेरिका के मंगल पर पिछले 61 साल में 58 मिशन भेजे जा चुके हैं। शुरुआत सोवियत संघ ने 10 अक्टूबर 1960 को की थी, पर सफलता अमेरिका को मिली। मंगल पर अब तक सबसे ज्यादा मिशन अमेरिका ने 29, दूसरे नंबर पर सोवियत संघ/रूस ने 22 और तीसरे नंबर पर ईयू ने 4 मिशन भेजे हैं। भारत, जापान, चीन और यूएई ने एक-एक मिशन भेजा है।

4 साल में 5 देश भेजेंगे मिशन; इनमें भारत का मंगलयान-2 भी

अगले चार साल में पांच देश मंगल पर मिशन भेजने वाले हैं। सबसे पहले ईयू और रूस मिलकर 2022 में एक्सोमार्स नाम का लैंडर-रोवर भेजेंगे। इसी साल जापान एक ऑर्बिटर और लैंडर भेजेगा। 2023 में अमेरिका का साइकी यान मंगल के बगल से निकलेगा। भारत 2024 में मंगलयान-2 भेजेगा। इसमें एक ऑर्बिटर और संभवतः एक लैंडर भी होगा।

कोरोना दुनिया में: डब्ल्यूएचओ बोला- मेलबर्न में नया क्लस्टर मिला, संक्रमितों के इलाज में काम आ सकती है अस्थमा की दवाई

वाशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.78 करोड़ से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 23 लाख 63 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक क्वारैंटीन होटल में 8 संक्रमित मिलने के बाद पूरे इलाके में टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रैसिंग बढ़ाने का फैसला किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में माना कि जिस होटल में दूसरे देशों से आए लोगों को क्वारैंटीन किया गया था वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आठ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे कम्यनिटी ट्रासमिशन का खतरा है, लिहाजा इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों से फौरन टेस्ट कराने को कहा गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि संक्रमित किन लोगों के संपर्क में आए थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लगातार 100 दिन तक लॉकडाउन रखा था। इस शहर में ही 800 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक होटल में क्वारैंटीन किए गए आठ लोगों को संक्रमित पाया गया है। इसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही यहां मास टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रैसिंग बड़े पैमाने पर शुरू की गई है।

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक होटल में क्वारैंटीन किए गए आठ लोगों को संक्रमित पाया गया है। इसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही यहां मास टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रैसिंग बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सभी वयस्कों के लिए कारगर है।

संगठन का यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यह कहते हुए इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी कि यह 65 साल से ऊपर के लोगों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन पर यह इफेक्टिव साबित नहीं हुई। अब डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यह साउथ अफ्रीका में पाए गए नए वैरिएंट के खिलाफ भी उतनी ही असरदार है, जितनी पुराने वायरस के खिलाफ। संगठन ने तो इसे लगाने की पैरवी भी की है। संगठन ने कहा है कि यह वैक्सीन दो डोजेस में दी जानी चाहिए।

कम होते जा रहा प्रदर्शनकारी किसान, सिंघु बार्डर पर अब बचे मात्र 93 ट्रैक्टर-ट्राली

बाहरी दिल्ली। सिंघु बार्डर पर एक तरफ जहां कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों में मायूसी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टरों की संख्या भी घट गई है। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर से सिंघु बार्डर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उस समय सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर- ट्राली लेकर प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे। उसके बाद से यहां इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी में उपद्रव करने के बाद से लगातार संख्या घटती जा रही है। तब से ट्रैक्टर वापसी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई ट्रैक्टर ट्राली लेकर गांवों के रास्ते से पंजाब का रुख कर रहा है तो कोई नरेला रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर जा रहा है।

प्रदर्शन के 76वें दिन बुधवार शाम तक प्रदर्शन छोड़कर इतने ज्यादा लोग घर जा चुके हैं कि अब सिंघु बार्डर पर मात्र 93 ट्रैक्टर-ट्राली व 14 ट्रक ही बचे हैं। इसमें से 32 ट्रैक्टर व चार ट्रक नरेला रोड पर खड़े हैं। इसके साथ ही यहां लगे टेंट भी उखड़ने लगे हैं। प्रदर्शन में शामिल कई उपद्रवियों ने जनवरी के आखिर में स्थानीय लोगों व पुलिस कर्मचारियों पर तलवारों से हमला कर दिया था। इस दौरान कई लोग घायल हुए थे। इसे देखते हुए प्रदर्शनकारी अब नरेला रेलवे स्टेशन की ओर पैदल जा तो रहे हैं, पर उन्हें भी डर लगा रहता है कि कहीं स्थानीय लोग उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जाने से रोक न दें।

लिहाजा वे अपने संगठन के झंडों को डंडों में लपेटकर चुपचाप जा रहे हैं, ताकि किसी को पता न लगे कि वह किस संगठन से हैं। सिंघु बार्डर पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) की ओर से धरना दिया जा रहा है। इस कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू हैं और महासचिव सरवन सिंह पंधेर। कमेटी के साथ केवल पंजाब के लोग ही हैं। हरियाणा या दिल्ली के लोग इनके साथ नहीं हैं। लिहाजा यहां पर पंजाब के प्रदर्शनकारियों की संख्या ही ज्यादा है। दिल्ली या हरियाणा से नाममात्र के ही लोग यहां पहुंचते हैं। वह भी मंच से संबोधित कर वापस चले जाते हैं।

दिल्ली से पंजाब तक किसान प्रदर्शनकारियों का यू टर्न, गद्दार के लिए जागी हमदर्दी; कर रहे रिहाई की मांग

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 79वें दिन पहुंच गया है। इस बीच लाल किसान हिंसा मामले में गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को लेकर किसान प्रदर्शनकारियों के रुख में बड़ा बदलाव आया है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू का नाम आने पर जो किसान प्रदर्शनकारी उसे गद्दार कह रहे थे, वह अब पटल गए हैं। आलम यह है कि किसान प्रदर्शनकारी अपने मंच से ही दीप सिद्धू को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले 26 जनवरी के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दीप के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होने से इनकार किया था।

वहीं, लाल किला उपद्रव मामले में गिरफ्तार पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू व अन्य उपद्रवियों को रिहा करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सिंघु बार्डर पर मार्च निकाला गया। मार्च में ज्यादातर नौजवान व महिलाएं ही शामिल थीं। इन्होंने दीप सिद्धू व पंजाब के गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना के पोस्टर हाथों में पकड़े हुए थे। इनका कहना था कि सरकार इनको जल्द से जल्द रिहा करे। हरियाणा से शुरू हुई मार्च सिंघु बॉर्डर तक पहुंची। यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब में अमृतसर के बाबा बकाला क्षेत्र से आए प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेताओं से उन्हें रिहा करवाने की मांग की। इस पर सतनाम सिंह पन्नू ने भी सिद्धू समेत सभी गिरफ्तार उपद्रवियों को रिहा करने की बात कही। बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू व महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद दीप को गद्दार बताया था और उससे कोई रिश्ता न होने की बात भी कही थी।

बर्ड फ्लू के डर से गर्म पानी में धोकर दिया जा रहा पक्षियों को दाना

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, इसके चलते चिड़ियाघर प्रबंधन टेंशन में है। ऐसे में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। पिछले दो दिनों से स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जगह-जगह कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पक्षियों को दिए जाने वाले दाने को भी धोकर दिया जा रहा है, जिससे पक्षियों तक कोई भी संक्रमण ना पहुंच सके।

पक्षियों के बाड़े के बाहर लगातार सफाई की जा रही है। चिड़ियाघर के अधिकारियों की माने तो इन दिनों चिड़िया, मोर, चील, तोते समेत अन्य पक्षियों का इन दिनों विशेष रख रखाव किया जा रहा है, जिसके चलते उनके खाने में दिए जा रहे दाने को भी साफ करके दिया जा रहा है। इसके लिए दाने को गर्म पानी से धोया जाता है। उसके बाद कीचन में काम करने वाले कर्मचारी दाने को सुखाते है और उसके पक्षियों के बाड़े तक पहुंचाते हैं। वहीं, पक्षियों को दिए जाने वाले फलों और मूंगफली के दानों को भी साफ करके दिया जा रहा है।

निदेशक रमेश कुमार पांडेय ने बताया कि सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन और स्वच्छता के लिए आदेशित किया गया है, जो पक्षियों के बाड़े के बाहर जाकर और चिड़ियाघर के खुले स्थानों पर जाकर सफाई कर रहे हैं। मंगलवार को चिड़ियाघर की ओर से चार स्थानों से पक्षियों के मल-मूत्र और पानी के सैंपल भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट बर्ड फ्लू संक्रमित आई थी।

बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू की हत्या पर भड़की एक्ट्रेस कंगना

नई दिल्ली। सामाजिक और राजनीतिक समेत तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने वालीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट ने दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है- रिंकू शर्मा के पिता के दर्द को महसूस करें और अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें।... किसी दिन कोई और हिंदू जय श्रीराम कहने पर सामूहिक रूप मार दिया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने लिखा है- सॉरी हम असफल रहे। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर देशभर के हिंदू संगठनों में उबाल है। लोगों ने इंटरनेट मीडिया के जरिये इंसाफ की मांग की है। वहीं, इससे पहले रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर हिंदू संगठन गहरा रोष प्रकट कर चुके हैं। संगठन से जुड़े लोगों ने मंगोलपुरी थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों ने भगवान राम के मंदिर निर्माण जैसे अनुष्ठान में खलल डालने का प्रयास किया है। रिंकू शर्मा की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि वह भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में जय श्री राम का उद्घोष कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने भी घटना को निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रिंकू का क्या कसूर था। सिर्फ यही न कि वह राम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहा था। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद अब दिल्ली में जिस प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया निधि समर्पण कार्यक्रम के दौरान दिखाई दे रही है, उससे पता चलता है कि राम विरोधी सेकुलर बिरादरी और कुछ मुस्लिम नेता समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिंकू की हत्या उसी जहर का परिणाम है। हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि वह सभी हत्यारों को गिरफ्तार करें और उन्हें कठोरतम सजा दिलाने की व्यवस्था करें। हिंदू समाज अब ऐसी हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। गौरतलब है कि बुधवार रात को मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की दर्जन भर लोगों ने मार डाला। जिस दौरान लोग उसे बुरी तरह घायल कर भागे तो वह जयश्रीराम के नारे लगा रहा था।

सड़कों पर अतिक्रमण और जाम से जल्द मिलेगी मुक्ति : इमरान हुसैन

नई दिल्ली। सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की मिल रही शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आराकशा रोड से लेकर कुतुब रोड तक पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द ही इन सड़कों पर फैले अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। मंत्री इमरान हुसैन के दौरे के दौरान करोलबाग के एसडीएम बलराम मीणा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस व निगम के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि सड़क पर कई स्थानों पर अवैध पार्किंग चल रही है, जिससे जाम लग रहा है। मंत्री ने क्षेत्रीय एसडीएम से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से रोड पर मुस्तैदी से अपना काम करने को कहा, जिससे जाम और अतिक्रमण की समस्या खत्म हो सके। इसके साथ ही मंत्री ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर व वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि कई बार एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे कि गंभीर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं, लोधी कालोनी के मीरा मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की ओर से किए जा रहे नाला निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों को लेकर वन विभाग ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है कि वह क्षतिग्रस्त किए गए एक पेड़ के बदले 100 पौधे लगाए और पांच साल तक उनका रखरखाव भी करें। गौरतलब हो कि पिछले साल इसी निर्माण कार्य के चलते करीब 30 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए थे और इस साल भी कुछ पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। पेड़ क्षतिग्रस्त करने की शिकायत मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी को पेड़ को बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

डीयू कार्यकारी-अकादमिक परिषद के चुनाव

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अकादमिक और कार्यकारी परिषद के चुनाव में शिक्षक संगठन अपनी जीत सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में किस शिक्षक संगठन के सिर जीत का सेहरा सजेगा यह काफी हद तक तदर्थ शिक्षक ही सुनिश्चित करेंगे। शायद इसीलिए चुनाव में इस बार तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। शुक्रवार को कार्यकारी परिषद की दो जबकि अकादमिक परिषद की 17 सीटों के लिए मतदान होगा। डीयू ने मतदान के दौरान शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 40 मतदान केंद्र बनाए हैं। पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहां पर तदर्थ शिक्षक न केवल शिक्षक संघ बल्कि कार्यकारी और अकादमिक परिषद के चुनावों में भी मतदान करते हैं। तदर्थ शिक्षक, शिक्षक प्रतिनिधियों से यह आश्वासन चाहते हैं कि वह जहां पर पढ़ा रहे हैं, वहीं उनको समायोजित किया जाए। शिक्षक मनोज कुमार कहते हैं कि डीयू के कई कालेजों में तदर्थ शिक्षक 15 साल से भी अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। स्थायी करने की उम्मीद है, लेकिन कब तक होंगे यह निश्चित नहीं है। प्रत्येक चार महीने बाद दोबारा नियुक्ति होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दौलतराम कालेज ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा विस्तार के लिए नवीनीकरण नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ एक भी शिकायत आने पर उन्हें बिना नोटिस दिए सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने आपत्ति जताई है। तदर्थ शिक्षकों ने बताया कि नोटिस में जिक्र है कि यदि किसी तदर्थ शिक्षक के खिलाफ कोई छात्र, टीचर इंचार्ज, प्रशासनिक अधिकारी शिकायत करते हैं या फिर विभाग का वर्कलोड कम होने पर शिक्षक की जरुरत नहीं महसूस होती है तो ऐसी परिस्थिति में बिना नोटिस दिए भी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दौलतराम कालेज में 100 से अधिक तदर्थ शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसे में यह नोटिस पढ़ने के बाद शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। डूटा अध्यक्ष राजिब रे ने प्राचार्य को एक पत्र लिखकर इस तरह के नोटिस को वापस लेने की मांग की है। उन्होने लिखा है कि, सिर्फ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। नवीनीकरण नोटिस में इस तरह के प्रावधानों का डूटा विरोध करता है एवं ये अस्वीकार है। मांग की गई है कि तत्काल नोटिस में से इसे हटाया जाए। दिल्ली सरकार से आग्रह है कि जब भी समग्र शिक्षा के शिक्षकों की वेकैंसी आए तो अतिथि शिक्षकों के तौर पर नियुक्त किए गए सभी समग्र शिक्षा के शिक्षकों को उसके तहत नियुक्ति दी जाए और जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है उन्हें भी बतौर अतिथि शिक्षक दिल्ली सरकार के स्कूलों में नियुक्ति दी जाए।

डीयू के कई कालेजों में तदर्थ शिक्षक 15 साल से भी अधिक समय से पढ़ा रहे हैं

स्थायी करने की उम्मीद है, लेकिन कब तक होंगे यह निश्चित नहीं है। प्रत्येक चार महीने बाद दोबारा नियुक्ति होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दौलतराम कालेज ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा विस्तार के लिए नवीनीकरण नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ एक भी शिकायत आने पर उन्हें बिना नोटिस दिए सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने आपत्ति जताई है। तदर्थ शिक्षकों ने बताया कि नोटिस में जिक्र है कि यदि किसी तदर्थ शिक्षक के खिलाफ कोई छात्र, टीचर इंचार्ज, प्रशासनिक अधिकारी शिकायत करते हैं या फिर विभाग का वर्कलोड कम होने पर शिक्षक की जरुरत नहीं महसूस होती है तो ऐसी परिस्थिति में बिना नोटिस दिए भी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

न्यूनतम और अधिकतम उम्र को लेकर नहीं मिलेगी छूट

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को नर्सरी दाखिले से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार छात्रों को नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए निदेशालय की तरफ से न्यूनतम व अधिकतम उम्र की छूट नहीं मिलेगी। निदेशालय ने प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए इस बार निर्धारित उम्र सीमा तय की है। इसके अनुसार नर्सरी में दाखिले के लिए छात्र की उम्र 31 मार्च 2021 को तीन साल या इससे अधिक और चार साल या इससे कम होनी चाहिए। केजी के लिए चार साल या इससे अधिक और पांच साल या इससे कम होनी चाहिए। वहीं, कक्षा 1 लिए पांच साल या इससे अधिक और छह साल या इससे कम होनी चाहिए। स्कूलों को निदेशालय की तरफ से उम्र सीमा को लेकर तय इन मानदंडो का ही पालन करना होगा। स्कूल अपनी तरफ से छूट नहीं दे सकते। हालांकि, बीते साल दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने अधिकतम और न्यूनतम उम्र को लेकर 30 दिन की अतिरिक्त छूट देने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्यों को दी थी। निदेशालय द्वारा तय किए गए मानदंडों के बाद अभिभावक दाखिला कराने में देरी न करें। क्योंकि इस बार उम्र सीमा को लेकर एक तय सीमा निर्धारित है। द्वारका स्थित श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्या नीता अरोड़ा ने बताया कि नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में अभिभावकों असमंजस में होंगे की उनके बच्चे की उम्र अभी कम है, तो वह अगले साल नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन ऐसा करने से शायद अगले वर्ष बच्चें की अधिकतम उम्र चार साल से ज्यादा हो जाए। तो अपने बच्चे के भविष्य के साथ लापरवाही ना बरतें। बल्कि ज्यादा परिश्रम करते हुए बहुत सारे स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए बच्चे की निर्धारित उम्र होने पर आवेदन करें। न्यू राजेंद्र नगर स्थित मानव स्थली स्कूल की प्रधानाचार्या ममता वी अरोड़ा ने कहा कि पहले के मुकाबले अब शिक्षा निदेशालय द्वारा उम्र की सीमा तय कर दी गई है। जिसका पालन सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से करना होगा। पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक पांच से छह साल होनी चाहिए। यदि उम्र एक दिन भी बढ़ी हुई है तो दाखिला मुश्किल है।

16 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, ट्रक में छुपाकर लाते थे गांजा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गांजे की तस्करी में दो गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मोहित यादव और सुभाष चंदर के रूप में हुई है। उनके पास से पांच बैग में रखा 116.50 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। तस्कर ट्रक से ओडिशा से गांजा लेकर दिल्ली आते थे। बाद में इसकी आपूर्ति दिल्ली-एनसीआर में की जाती थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच मादक पदार्थ की तस्करी में लगे तस्करों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में गत दिनों दिल्ली से कई गांजा तस्करों को दबोचा भी गया था। तस्करों से पूछताछ में पता चला था कि गिरोह के दो सदस्य 10 फरवरी को ट्रक से गांजे की खेप लेकर दिल्ली आने वाले हैं। इसकी सूचना पर पुलिस की टीम ने डीएनडी फ्लाइओवर के समीप से दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में ट्रक से गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा प्राप्त करते थे। आरोपित मोहित यादव चालक है और गत दो महीने से तस्करी में लिप्त था। जबकि अन्य तस्कर सुभाष चंदर ट्रक का हेल्पर है। जल्द पैसा कमाने के चक्कर में वह मोहित के साथ मिलकर गांजे की तस्करी करने लगा था। वहीं, ऑटो पार्ट्स की दुकान से रिवॉल्वर, पांच कारतूस और पंद्रह हजार रुपये चोरी करने के आरोपित दीपांशु को सब्जी मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से रिवाल्वर और तीन कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। दो कारतूस उसने नशे में चला दिए और चोरी का पैसा मसूरी की सैर में खर्च कर दिया। चोरी की वारदात में उसके सहयोगी रोहन की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि करोलबाग निवासी सुरेंद्र कुमार जैन की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज हुआ था। घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो संदिग्धों की पहचान की थी। आरोपित कुम्हार वाली गली का निवासी है और नशे की लत के इलाज के लिए फरीदाबाद के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था।

दिल्ली के कोरोना योद्धाओं के परिवार को मिलेगा निःशुल्क सरकारी घर

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के स्वजन के लिए निश्शुल्क सरकारी आवास देने का एलान किया है। दक्षिणी निगम के नेता सदन नरेंद्र चावला ने सदन की विशेष बैठक में वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान और 2021-22 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे निगम में कार्यरत कोरोना योद्धा अपने परिवार के भविष्य की चिंता किए बगैर मानव सेवा कर सकते हैं। इससे पूर्व निगम ने अपने कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। नरेंद्र चावला ने बताया कि दक्षिणी निगम में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले 16 कोरोना योद्धाओं की कोरोना से जान जा चुकी है। इनमें से 15 कोरोना योद्धाओं के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दे दी गई है। वहीं, नौ परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी भी दे दी गई है। शेष परिवारों में आश्रितों के नाबालिग होने या अन्य कारणों की वजह से नौकरी नहीं मिल सकी। इनके आवेदनों पर विचार होगा। महामारी के दौरान सफाई कर्मियों से लेकर शिक्षकों, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) और अन्य कर्मचारियों ने राशन वितरण से लेकर, संक्रमितों के घरों के आस-पास डोर टू डोर सर्वे किया है। सफाई कर्मचारी भी होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों के घरों से कचरा लेकर जाते थे। बजट में नेता सदन ने दैनिक वेतन भोगियों को भी तोहफा दिया है। निगम में 31 मार्च 2017 तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा। इससे पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग (डेम्स), शिक्षा, स्वास्थ्य, अभियांत्रिक आदि विभागों के सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

पर्यावरण मंत्रालय का पूर्व उप निदेशक रिश्वत लेने के लिए दोषी करार

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व उप निदेशक नीरज खत्री को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया है। खत्री पर तमिलनाडू की एक कंपनी को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) स्थापित करने के लिए एनओसी के बदले सवा चार लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप था। इस संबंध में सीबीआइ ने एक मार्च 2016 को केस दर्ज किया था। खत्री के अलावा वी.वी मिनर्लस, इसके पार्टनर एस वैकुंडाराजन और लाइजन आफिसर शुभलक्ष्मी को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा पर 15 फरवरी को विशेष न्यायाधीश नीरजा भाटिया की अदालत में बहस होगी। विशेष अदालत ने नीरज खत्री को भ्रष्टाचार का आदि बताया है। क्योंकि 2017 में भी विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में खत्री को तीन साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी थी। विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में सीबीआइ ने कहा था कि हरियाणा के रोहतक निवासी नीरज खत्री पर्यावरण मंत्रालय में 2012 में बतौर उप निदेशक तैनात थे। वी.वी मिनर्लस तमिलनाडू के तिरुनेलवेली जिले में एसइजेड स्थापित करना चाहती थी। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, जबकि पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी नहीं मिली थी। इसके लिए एस वैकुंडाराजन ने शुभलक्ष्मी को नियुक्त किया और शुभलक्ष्मी ने नीरज खत्री से संपर्क किया। सीबीआइ के आरोपपत्र के मुताबिक कंपनी की तरफ से चार लाख 15 हजार रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट तमिलनाडू स्थित वीआइटी यूनिवर्सिटी के नाम जमा कराया गया। इस यूनिवर्सिटी में नीरज खत्री के बेटे सिद्धार्थ ने बीटेक में दाखिल लिया था और कंपनी की तरफ से जमा कराया गया बैंक ड्राफ्ट उसकी फीस के लिए था। आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि 5 जुलाई 2012 को नीरज खत्री अपने बेटे को यूनिवर्सिटी में छोड़ने गए थे। उनके दिल्ली से जाने और वापस आने की हवाई टिकट भी आरोपित कंपनी ने ही बुक की थी। यह सब खर्च कर कंपनी ने एनओसी हासिल की थी। नीरज खत्री पर 2013 में ओडिशा की एक पावर कंपनी को एनओसी देने के बदले सात लाख रुपये रिश्वत लेने का भी आरोप लगा था। इस मामले में विशेष सीबीआइ अदालत ने नवंबर 2017 में तीन साल जेल की सजा दी थी। विशेष अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था। हालांकि बाद में इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब फिर से रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने के बाद विशेष अदालत ने नीरज खत्री को भ्रष्टाचार का आदि बताया है।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले पढ़ लें यह खबर, जान लें यह फायदे की बात

नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और पर्यावरण के अनूकुल वाहनों को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं तो दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार तो बड़ी राहत देने का एलान कर चुकी है। दरअसल, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। इसके तहत स्विच अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इस दिशा में सरकार दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदने वाले को ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद करेगी। जो लोग ऋण लेंगे उन पर लगने वाले ब्याज में पांच फीसद की सरकार आर्थिक मदद देगी।

इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग सहित कई दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद कैलाश गहलोत ट्वीट करते हुए बुधवार को जानकारी दी कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लांच किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हर आम आदमी तक इलेक्ट्रिक वाहन की पहुंच हो। इसके लिए जल्द दोपहिया और तिपहिया वाहन की खरीदारी करने वालों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और दिल्ली वित्तीय निगम की सूची में सम्मिलित वित्त प्रदाता से ऋण पर पांच फीसद ब्याज की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऋण लेने की प्रक्रिया को भी लचीला बनाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में चार पहिया वाहनों की खरीद पर अधिकत 1.50 लाख रुपये सब्सिडी का एलान किया गया है। वहीं, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जा रही है। ऐसा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करने के मकसद से किया गया है। दरअसल, हर साल दिल्ली में अक्टूबर से लेकर मार्च तक वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में ही रहता है। यह खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है।

संपादकीय

आंदोलन को मिली खाप से ताकत

दो दिन पहले, बुधवार को हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में प्रांत की सभी 50 खापों की एक सर्वखाप पंचायत हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की ही मांगें दोहराई गई हैं। भारतीय किसान यूनियन को मंच देकर सर्वखाप पंचायत ने आंदोलनकारी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में, सवाल यह पूछा जाने लगा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में क्या इन पंचायतों की भी भूमिका होगी? चूंकि खापों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है (बैठक अथवा रैली का आयोजन अलग बात है), इसलिए केंद्र सरकार से बातचीत में खाप के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, ऐसा नहीं लग रहा। वार्ता की मेज पर तो वही संगठन बैठेंगे, जो अब तक केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बात करते रहे हैं। फिर भी, खाप पंचायत एक रास्ता बना सकती है और उसे यह भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। खाप पंचायतें किसान नेताओं से जिद व अहं न पालने और वार्ता में 'एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे' की नीति अपनाने को समझा सकती हैं। हर समस्या का समाधान देर-सबेर निकलता है, इसलिए इस मसले का भी निकलेगा ही, लेकिन इस बीच सामाजिक ताना-बाना, राष्ट्रीय छवि और आपसी सद्भाव कायम रखना कहीं ज्यादा जरूरी है।

मुगल काल से उत्तर भारत के जाटों की खाप पंचायतें एक सामाजिक ग्राम्य गणतंत्र रही हैं। उत्तर मुगल काल में जब अफगान आक्रांता थोड़े-थोड़े अंतराल पर सिंध पार करके पंजाब को रौंदते हुए सशस्त्र बलों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ते थे, तब अपनी स्त्रियों, बच्चों और संपत्ति की रक्षा के लिए जाटों ने समूह बनाने शुरू किए थे। प्रारंभ में ये समूह गोत्र पर आधारित थे। जाटों में गोत्र की व्यवस्था उतनी ही पुरानी है, जितनी जाति। अपना डीएनए खास बनाए रखने के लिए जाट अपने बच्चों के शादी-ब्याह ऐसे दूसरे गोत्रों में करते हैं, जिनसे उनकी मां और पिता के गोत्र न टकराते हों। इस व्यवस्था से उनका सामाजिक विस्तार भी होता गया और समानता व एकता की भावना भी बलवती होती गई।

बाद के दिनों में गोत्र विशेष के छोटे-मोटे विवादों का निपटारा इनकी पंचायतों में होने लगा। खाप का ढांचा पिरामिडीय आकार का रखा गया है। नजदीकी भाई अपना कुटुंब बनाते हैं, कुटुंब मिलकर थोक (पट्टी) निर्मित करते हैं, थोक मिलकर थाम्बा गठित करते हैं, और अंत में उस गोत्र के थाम्बे मिलकर खाप का गठन करते हैं। सभी खापें मिलकर एक सर्वखाप का गठन करती हैं। कंडेला में यही सर्वखाप पंचायत हुई थी। वैसे, सबसे बड़ी सर्वखाप पंचायत 1936 में बालियान (जिसके प्रमुख नरेश टिकैत हैं) खाप के सोरम गांव में हुई थी। उसमें किसानों ने गांधीजी के आह्वान पर देश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का फैसला किया था। एक बात समझने की जरूरत है। जाटों की नजर में जमीन बहुत ही मूल्यवान होती है। एक जाट कितने भी महंगे बंगले में रहता हो, एलीट क्लब का सदस्य हो, करोड़ों के पैकेज वाली सैलरी कमाता है, पर दूसरों से बातचीत में अपने पास गांव में पैतृक जमीन होने की बात पर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता है। खाप ग्रामीणों का संगठन होता है, इसलिए उनके पास किसान नेता व राजनेता अपना मनोबल, संख्या बल और शक्ति प्रदर्शन हासिल करने जाते हैं। ग्रामीण किसान भावुक और भोला-भाला होता है। वह आसानी से भावनाओं में बह जाता है। इसका फायदा भी आंदोलन के नेता उठाने से नहीं चूकते। राजनेता खापों के किसी काम नहीं आते, लेकिन उनका समर्थन जरूर अपने आंदोलन में जान फूंकने के लिए लेते रहते हैं।

बहरहाल, खापों के किसान आंदोलन में शामिल हो जाने के बाद आंदोलन उग्र तो नहीं होगा, लेकिन खापों की सक्रियता से यह आंदोलन कुछ दिन अथवा माह लंबा जरूर खिंच जाएगा। लाल किले की शर्मनाक घटना ने ग्रामीणों (खापों के मुख्य स्रोत) को भी अंदर तक झकझोर दिया था। हॉलीवुड के सितारों और कनाडा की रैलियों की कवरेज इन ग्रामीणों पर भी सीधा असर डाल रही हैं। जिन किसान परिवारों का एक भी सदस्य सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है, पुलिस में रहकर कानून-व्यवस्था संभालने में जुटा है, वह कतई नहीं चाहेगा कि किसान आंदोलन अपने मार्ग से भटककर अपने में राष्ट्रद्रोही तत्वों को शामिल करे या हिंसक हो जाए। जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। वह वार्ता के सभी माध्यम खुले रखे। हमारी कृषि शिक्षण संस्थाएं विश्व-स्तरीय हैं। यहां अध्ययन कर चुके छात्र और अध्ययन कराने वाली फैकल्टी दुनिया भर में पढ़ा रही हैं या शोध-कार्यों में जुटी हुई हैं। इन्हें शामिल करके किसानों के हित के मामले उनको समझाए जा सकते हैं। किसानों के दिल में बैठ गई या बिठाई गई ये बातें निकालनी पड़ेंगी कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के हित साधने के लिए ये कानून बने हैं। किसानों के हित के प्रावधान उन्हें समझाने चाहिए। बिजली, खाद व पानी की किल्लत और खाद्य पदार्थों का बाजार न मिलने जैसी समस्याएं भी राज्य सरकारों को साथ लेकर सुलझाने की जरूरत है। कृषि राज्य का विषय है। इसलिए समस्या के समाधान की जिम्मेदारी अकेले केंद्र की नहीं है। किसान आंदोलन एक खास तबके या जाति द्वारा चलाया जा रहा है, यह भ्रम तोड़ना होगा, और इसकी जवाबदेही आंदोलन के नेताओं की है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आजादी के बाद के समूचे भारत वर्ष के निर्विवादित किसान नेता किसानों को एक वर्ग मानकर उनकी लड़ाई लड़ते थे। चौधरी चरण सिंह अपने समूचे राजनीतिक जीवन में लोक-व्यवस्था बनाए रखने और सांविधानिक संस्थाओं के सम्मान व प्रतीकों की सुरक्षा के हिमायती थे। उम्मीद है, किसान बिरादरी उनकी इस विरासत को बनाए रखने को कृत संकल्पित होगी।

प्रवीण कुमार सिंह

भारत की वैक्सीन रणनीति ने पश्चिमी देशों की हवा निकाल दी

भारत की वैक्सीन रणनीति ने पश्चिमी वर्चस्व वाले विमर्श की हवा निकाल दी है। दुनिया भारत को वैक्सीन के प्रभावी एवं किफायती आपूर्तिकर्ता की दृष्टि से तमाम उम्मीदों के साथ देख रही है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फैरेल ने इन उम्मीदों को इन शब्दों में बयान किया कि वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन बनाई जा रही हैं, लेकिन हर एक देश की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता किसी देश में है तो वह भारत है।

दुनिया के अधिकांश इलाके अभी भी कोरोना के चंगुल में फंसे हैं। उससे बचने के लिए कई जगहों पर नए सिरे से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर देश कोविड-19 आपदा से निपटने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन की मांग आसमान छू रही है। इन हालात में इसकी गुंजाइश कम ही हो जाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। इस स्थिति के बावजूद जब भारत ने हाल में हिंद महासागरीय देशों को लाखों की तादाद में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई तो उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आर्किषत किया। बीते हफ्ते म्यांमार से लेकर बांग्लादेश और मॉरीशस से लेकर सेशेल्स तक लाखों की तादाद में भारत में र्निमत वैक्सीन पहुंचाई गई हैं। पांच लाख वैक्सीन की खेप श्रीलंका भी पहुंची है। अन्य देशों को भी लाखों-लाख वैक्सीन भेजने की तैयारी जारी है।

भारत द्वारा दिया जा रहा वैक्सीन का यह उपहार बेमिसाल है। किसी भी अन्य देश ने लाखों की तादाद में दूसरे देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई है। यहां तक कि उस चीन ने भी नहीं, जो अपनी धरती से निकले वायरस के बाद नष्ट अपनी छवि सुधारने के लिए वैक्सीन कूटनीति की जुगत में जुटा है। भारत द्वारा दी जा रही इस भेंट ने भारत की वैक्सीन बनाने की व्यापक क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। इस मामले में भारत का मानवीय पहलू और मुखरित होकर उभरता है, क्योंकि उसने अपने नागरिकों के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के मात्र चार दिन बाद ही वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी शुरू कर दी। टीका हासिल करने वाले देश भी पुलकित हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने इसे परोपकार का पर्याय बताते हुए कहा कि अपनी

आवश्यकता की पूंति से पहले ही अनमोल वस्तुएं साझा की जा रही हैं।

भारत पहले चरण में 30 करोड़ की आबादी को टीका लगाने के लिए तत्पर है। ऐसा करने वाला वह पहला बड़ा विकासशील देश है। इसका घरेलू कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। इस मामले में भारत के साथ जुड़े ताकतवर पहलुओं में से एक यह है कि विभिन्न बीमारियों के प्रतिरोध में काम आने वाली दुनिया की 60 प्रतिशत से अधिक वैक्सीन भारत में ही बनती हैं। वैक्सीन निर्माण में अपनी इस महारत का लाभ वह अपने पड़ोसियों को मुफ्त वैक्सीन के रूप में मानवीय कूटनीति को मूर्त रूप देने में उठा रहा है। यह भारत के व्यापक एवं विस्तृत वैक्सीन विनिर्माण ढांचे का ही दम है कि फिच सॉल्यूसंश ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत अपने स्वास्थ्यकर्मियों और बूढ़ी आबादी के एक बड़े हिस्से को इस साल के मध्य तक टीका लगवाने में सक्षम होगा। इस मोर्चे पर भारत अपने से कहीं छोटे दक्षिण कोरिया जैसे देश से भी बाजी मार ले जाएगा।

भारत पहले ही कई देशों को एक अरब वैक्सीन डोज देने पर सहमति जता चुका है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के लिए भी योगदान देगा। इस पहल का मकसद गरीब देशों को टीका उपलब्ध कराना है। फिलहाल भारत दो वैक्सीन बना रहा है। इसमें एक तो एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन है। दुनिया में वैक्सीन के सबसे बड़े विनिर्माता सीरम को एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा अनुबंध भी दिया है। जनवरी की शुरुआत में जब भारत ने वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति प्रदान की, तब उससे पहले ही सीरम द्वारा कोविशील्ड की छह से आठ करोड़ खुराक तैयार कर दी गई थीं। इसका अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ वैक्सीन साझा करने के लिए भारत के पास विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त भारत में कोरोना के मामलों की लगातार घटती संख्या ने भी मोदी सरकार को वैक्सीन कूटनीति के लिए कहीं अधिक गुंजाइश दे दी है।

कोरोना के मामलों में तेज गिरावट से स्पष्ट है कि यहां अब यह महामारी पिछड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन द्वारा वैक्सीन पेशकश को लेकर प्रतिस्पर्धा ने भारत की भूमिका को अहम बना दिया है। महामारी की शुरुआत से ही भारत ने कोविड-19 टेस्ट किट्स, पीपीई और कोरोना वायरस के लक्षणों के बाद उपचार में काम आने वाली दवाओं का भारी मात्रा में निर्यात किया। जेनेरिक दवाओं के मामले में भारत पहले से ही दुनिया में अव्वल है।

इसके उलट पूरी महामारी के दौरान चीन ने दवा उद्योग में अपनी महारत को वाणिज्यिक हितों की पूंति के लिए इस्तेमाल किया और उसने अभी तक बहुत कम संख्या में ही वैक्सीन देने का एलान किया है। हालांकि विकासशील देशों को अपनी वैक्सीन बेचने की उसकी कोशिशों को तब तगड़ा झटका लगा, जब ब्राजील में अंतिम चरण के परीक्षण में उसकी वैक्सीन महज 50 प्रतिशत प्रभावी साबित हुई। फिर ब्राजील ने वैक्सीन के लिए भारत की ओर ही रुख किया।

सवाल यह है कि क्या भारत की वैक्सीन कूटनीति उसके अंतरराष्ट्रीय हितों को पोषित करने में सहायक होगी? भारत-चीन सीमा पर भारी तनातनी है। भारत के पड़ोस में भी चीन अपनी शातिर बिसात बिछा रहा है। भारत को उम्मीद है कि जहां चीन को महामारी के जनक के रूप में वहीं भारत को इस महामारी से राहत दिलाने वाले देश के रूप में याद किया जाएगा। चीन अभी भी भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है, ऐसे में नई दिल्ली अपनी वैक्सीन डोनेशन से बनी भावनाओं को अपने पक्ष में भुना सकती है।

भारत की वैक्सीन रणनीति ने पश्चिमी वर्चस्व वाले विमर्श की हवा निकाल दी है। दुनिया भारत को वैक्सीन के प्रभावी एवं किफायती आपूर्तिकर्ता की दृष्टि से तमाम उम्मीदों के साथ देख रही है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फैरेल ने इन उम्मीदों को इन शब्दों में बयान किया कि वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन बनाई जा रही हैं, लेकिन हर एक देश की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता किसी देश में है तो वह भारत है। वास्तव में यह भी एक विरोधाभास है कि भारत के मुकाबले कई धनी देशों विशेषकर यूरोपीय संघ के देशों में टीकाकरण की रफ्तार बहुत सुस्त है। स्पष्ट है कि इस महामारी के अंत में भारत के वैक्सीन उद्योग की केंद्रीय भूमिका होगी।

आंसुओं का मोल

मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। देश ने इससे पहले भी कई मौकों पर उन्हें भावुक होते देखा है लेकिन यह पहला मौका है जब किसी विपक्षी नेता के योगदान की चर्चा करते हुए दो-दो बार उनका गला रुंध गया। अपने देश में संसद के अंदर ही नहीं बाहर भी ऐसे दृश्य सामने आते रहे हैं जब राष्ट्र हित, लोकतंत्र और इंसानियत के जज्बे के सामने राजनेताओं के दलीय मतभेद बौने साबित हुए हैं। चाहे राजीव गांधी द्वारा बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के सरकारी खर्च पर अमेरिका में इलाज की व्यवस्था किए जाने का मामला हो, या उनके बाद आए कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा कश्मीर के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र में देश का पक्ष रखने की जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुख अब्दुल्ला को सौंपने का- ये बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नीतियों को लेकर मतभेद जरूर रहे हैं, पर आपसी अविश्वास कभी नहीं रहा।

द्विपक्षीय सहयोग और सामंजस्य की यह ठोस जमीन तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही, जिसे बाद के प्रधानमंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने आगे बढ़ाया। इस सिलसिले में यह भी याद करना जरूरी है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इमर्जेंसी के दौरान न केवल आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे, बल्कि विपक्ष से संवाद के सारे पुल ध्वस्त करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण समेत सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद 1977 के आम चुनाव में पराजित होने के बाद जब इंदिरा गांधी जेपी से मिलने गईं तो जेपी ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। इंदिरा गांधी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन जेपी की चिंता यह थी कि बिना वेतन के इंदिरा का घर कैसे चलेगा। इंदिरा गांधी ने भी उस चिंता का सम्मान करते हुए बताया कि पिताजी (जवाहरलाल नेहरू) की किताबों की रॉयल्टी आ जाती है और कुछ सेविंग भी है, उससे काम चल जाएगा। ये केवल औपचारिकताएं नहीं, उस राजनीतिक सद्भाव के उदाहरण हैं जिससे हमारे लोकतंत्र की जड़ों को पोषण मिलता है।

चिंता की बात यह है कि संसद में समय-समय पर दिखाई देने वाले भावुक पलों के बावजूद राजनीति का यह सद्भाव हाल के वर्षों में कम होता गया है। इसका असर न केवल ऊपरी स्तर पर पक्ष-विपक्ष के नेताओं द्वारा एक-दूसरे पर की जाने वाली तीखी टिप्पणियों में दिखता है बल्कि समाज में बिल्कुल नीचे तक मौजूद तीखे विभाजन में भी झलकता है। राजनीतिक धड़ों के बीच ऐसी दूरी, इतना अविश्वास ठीक नहीं है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इस बीमारी का इलाज करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से दोनों पक्षों की है, लेकिन सरकार का हाथ हमेशा ऊपर होता है, इसलिए उससे उम्मीद भी ज्यादा की जाएगी। बेहतर होगा

बाइडन काल में पेरिस समझौता, कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रति अमेरिका फिर से गंभीर दिख रहा

परिवार के ज्येष्ठ पुत्र से सबको बड़ी उम्मीद होती है। अपवादों को छोड़ दें, तो माना जाता रहा है कि अगर घर-कुल का बड़ा बेटा लायक निकल गया तो छोटे भी उसका अनुसरण कर सकते हैं और उनके भी लायक बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके उलट भी मामले होते हैं, लेकिन ये मान्यता टूट नहीं रही है। मान्यताओं को वास्तविकता के चश्मे से देखे जाने वाले देश में एक और समझ है- वसुधैव कुटुंबकम। यानी पूरी धरती को अपना परिवार समझने की। अगर हम इस मान्यता पर आधुनिक दुनिया को एक परिवार मानें तो इस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र अमेरिका हुआ।

लिहाजा अमेरिका के आचार-विचार और व्यवहार से पूरी दुनिया प्रेरित और प्रोत्साहित होती है, लेकिन अगर यही देश दुनिया के हित के प्रतिकूल कोई हरकत कर देता है तो सवाल स्वाभाविक हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बचकाने फैसलों के लिए पूरे कार्यकाल के दौरान किरकिरी कराते रहे। इन्हीं में से एक पेरिस जलवायु समझौते से देश को बाहर करने का भी उनका फैसला रहा।

दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के दंश से बचाने के लिए किया गया यह वैश्विक करार अमेरिका के इन्कार से हीलाहवाली की भेंट चढ़ता दिखा। जिस अमेरिका की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मात्र भारत से करीब 10 गुना ज्यादा हो, भला उसके कार्बन उत्सर्जन की कटौती से मुंह फेरने पर भारत जैसे छोटे भाई क्यों अपना दायित्व निभाएंगे। नए राष्ट्रपति बाइडन ने ट्रंप की भूलों को सुधारने का काम शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा पेरिस जलवायु समझौते में वह अमेरिका को फिर से शामिल कर रहे हैं व तय लक्ष्यों के तहत देश में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नियम को लागू करेंगे।

दुनिया के किसी भी समझदार इंसान से पूछिए कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो वह कोरोना नहीं बोलेगा। कोरोना तो तात्कालिक है। दीर्घकालिक समस्या ग्लोबल वार्मिंग बन चुकी है, जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष नुकसान इस महामारी से कई गुना अधिक दुनिया को हर साल उठाना पड़ता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाकर हम मानवता का कल्याण कर सकते हैं।

दुनिया ने इसे माना और संयुक्त राष्ट्र की छतरी के नीचे सभी देशों के बीच कई बार अहम समझौते हुए। इसी क्रम में दिसंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन में 196 देशों के बीच एक समझौता किया गया, जिसमें पूर्व औद्योगिकीकरण काल के मुकाबले तापमान दो डिग्री सेल्सियस नीचे रखे जाने का लक्ष्य रखा गया। खास बात यह रही कि समझौते में सभी देशों को उनकी प्रकृति के हिसाब से कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा गया। यह बात भी सामने आई कि दशकों से सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन कर औद्योगिक देश अब विकसित देश बन चुके हैं, लेकिन जब गरीब मुल्कों के विकास की बात आई तो उन पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य थोपा जा रहा है।

लिहाजा समझौते में यह कहा गया कि विकासशील देश तेजी से विकास करें, इसके लिए विकसित देश तकनीकी स्थानांतरण के रूप में उनकी मदद करेंगे। उन तकनीकों के इस्तेमाल से गरीब मुल्क अपनी जरूरत के मुताबिक आर्थिक विकास के लक्ष्य हासिल कर सकेंगे और इस समझौते के अनुसार बाध्यकारी कार्बन कटौती के लक्ष्य को भी हासिल कर सकेंगे। इस वार्ता में शामिल दोनों ही प्रकार के देशों यानी गरीब और अमीर को यह बात सुहा गई और समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। पर्यावरणविदों और विज्ञानियों ने मानवता के कल्याण में इसे ऐतिहासिक दिन बताया। लेकिन सारी खुशी काफूर तब हो गई, जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से अपना हाथ खींच लिया। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी जलवायु परिवर्तन जैसी अवधारणा को शायद मनगढ़ंत मानती रही है, तभी उसके पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश भी इस सिद्धांत को विज्ञानियों की एक काल्पनिक कहानी मानते रहे। जून, 2017 में अमेरिका इस संधि से अलग हो गया।

बड़े भाई के रूप में अमेरिका का इस समझौते से फिरने का भारत जैसे तमाम छोटे भाइयों को क्या संदेश गया होगा, ये हर कोई समझता है। वैसे भारतीय जनमानस हमेशा से मितव्ययी रहा है। आज भी वह वाहन का चयन माइलेज देखकर ही करता है, हालांकि यहां भी एक प्रभावी वर्ग उभर आया है जो हर कीमत की और हर स्तर के वाहनों को खरीदने में सक्षम है। अमेरिका के पास इफरात पैसा है। वह अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर अकूत धन देता है, जिसे बेहिचक खर्च करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती है।

तभी वहां की सड़कों पर आप बड़े इंजन वाले भारी-भरकम वाहनों से आम लोगों के आवागमन को व्यापक रूप से देख सकते हैं, जो बहुत अधिक ईंधन की खपत करते हैं। ऐसे में अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अगर ट्रंप ने जलवायु नीति से किनारा कर लिया, तो भला उसके छोटे भाई क्यों न सवाल खड़े करें।

अंत भला तो सब भला। तब अमेरिका के उस कदम का एक हद तक अन्य बड़े उत्सर्जक देशों ने मौन समर्थन किया था, कुछ ही मुखर हो पाए थे, लेकिन अब बड़ा भाई फिर से इस समझौते में शामिल हो चुका है तो दुनिया के देशों का भरोसा फिर से पेरिस जलवायु संधि को लेकर मजबूत होगा और तमाम बड़े उत्सर्जक देशों में यह संदेश जाएगा कि वे अपने तय लक्ष्यों को हासिल करें और गर्म होती धरती के विनाशकारी दुष्प्रभावों से दुनिया को बचाएं।

भारत की क्षमता से परिचित होती दुनिया, वैक्सीन कूटनीति के बजाय टीका-मैत्री पर जोर

ऐसे में चीन व अन्य अमीर व शक्तिशाली देश टीके की आड़ में उपचार की पूरी कीमत वसूलने में लगे हैं। चीन ने तो हृदयहीनता का परिचय देते हुए बांग्लादेश से ड्रग ट्रायल के खर्च की भी मांग कर डाली थी। भारत भी ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने वैक्सीन के बहाने नाजायज प्रभाव जमाने की बजाय निस्वार्थ उदारता दिखाई और छोटे व बड़े देशों की समान रूप से मदद करने में लगा है। इसीलिए इसे टीका कूटनीति की बजाय टीका-मैत्री कहना कहीं ज्यादा उचित होगा।

भारत में कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत के साथ मानवता को निरोगी बनाए रखने के संकल्प ने गति पकड़ ली है। पूरी दुनिया में यह टीकाकरण बड़ी चुनौती इसलिए है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अमेरिकी टीका निर्माता फाइजर बायोएनटेक के बने टीके की समय पर आपूर्ति नहीं होने से टीकाकरण करा रहे दुनिया के 80 प्रतिशत देशों में संकट खड़ा हो गया है। रूस व चीन के इतर दुनिया में सबसे पहला कोरोना टीका फाइजर ने तैयार किया था, जिसकी खुराकों को बड़ी संख्या में ज्यादातर अमीर देशों ने अनुबंध कर लिया था। लेकिन समय पर टीके की आपूर्ति नहीं होने के कारण टीकाकरण लंबित हो रहा है। इटली और पौलेंड ने फाइजर पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। रोमानिया को अनुबंध के मुताबिक टीके की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। चेक रिपब्लिक का भी यही हश्र हुआ है। कनाडा को भी यह टीका समय पर नहीं मिला।

इन सबके बावजूद भारत में टीकाकरण न केवल सुचारू रूप से चल रहा है, बल्कि कई देशों को टीका दान के रूप में दे दिए जाने के बावजूद दूसरे देशों को अनुबंध के मुताबिक टीके की खुराकों की प्रदायगी बराबर की जा रही है। टीका के क्षेत्र में सबसे पहले आत्मनिर्भर बनकर भारत ने वैक्सीन कोविशील्ड बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स को दान में दे दी है। इसके साथ ही सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को और ब्राजील जैसे देशों को व्यापारिक

समझौतों के तहत टीकों की खेप पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो हवाई अड्डे पर जब विमान वैक्सीन लेकर पहुंचा तो उसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इस वैक्सीन कूटनीति की तारीफ अमेरिका की नई बाइडन सरकार ने भी की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत सच्चा मित्र है, जिसने दवा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को महामारी से मुक्ति के लिए कोरोना टीका भेजने की शुरुआत कर दी है।

वैक्सीन के बहाने भारत ने कोविशील्ड और को-वैक्सीन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन शुरू करके दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब भारत फार्मास्युटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पड़ोसी देशों को उपहार में टीका उपलब्ध कराकर भारत ने मानवता के प्रति अपनी भावना को दर्शाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा, कोरोना महामारी में नरेंद्र मोदी का अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहायता के लिए आरंभ से ही दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर शोध, विचार-विमर्श, टीका निर्माण और वितरण पर अपनी विलक्षण क्षमता का प्रदर्शन किया है।

पिछले लगभग एक साल से इस महामारी ने दुनिया भर में त्रहिमाम मचा रखा है, लेकिन इसने चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान के नए द्वार खोले, जिनके सकारात्मक परिणाम निकले और भारत जैसे विकाशील देश इस कड़ी में अग्रणी देश साबित हुए। इसके कूटनीतिक परिणाम भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में नए आकार में दिखाई देंगे और भारत के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते यह क्षेत्र हमेशा भारत के लिए चिंता का कारण रहा है। नेपाल को भी दान के रूप में वैक्सीन देने के बाद वहां के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। चीन के प्रबल समर्थक रहे वहां के निवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्रोही गुट ने प्राथमिक सदस्यता रद कर दी है। इसे टीका कूटनीति का पर्याय माना जा रहा है। इसी तरह चीन ने जब बांग्लादेश से वैक्सीन के परीक्षण का खर्च मांगा तो बांग्लादेश ने चीन से सौदा रद कर दिया। ढाका में चीन बांग्लादेश को सिनोफॉर्म वैक्सीन देने का सौदा कर रहा था, लेकिन उसने इस सौदे की शर्तों में क्लीनिकल ट्रायल में होने वाले खर्च की मांग भी कर डाली। इस शर्त को बांग्लादेश ने मानने से इन्कार कर दिया। इधर भारत ने बांग्लादेश को मानवता के नाते एवं द्विपक्षीय संबंधों के चलते टीके की 20 लाख डोज उपहार में दी है। साथ ही, अनुबंध के तहत टीके की तीन करोड़ खुराकें भेजी जानी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रति कृतज्ञता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो वार्ता के जरिये धन्यवाद दिया। साफ है, भारत की कूटनीति इस टीके के जरिये वैश्विक स्तर पर मजबूत व फलदायी होने जा रही है।

नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों के प्रति प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मानवीय उदारता दिखाई है। इसी क्रम में भारत ने एक साझा उपग्रह उपहार में दिया था, जिसे पाकिस्तान को छोड़ सभी दक्षेश देशों ने सराहा था। पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भले ही दक्षेश संगठन लगभग निष्क्रिय है, लेकिन बिम्सटेक के मंच के माध्यम से भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, तकनीक, वित्त और अब दवा के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ा रहा है। महामारी से मुक्ति के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और अब टीके व अन्य जरूरी उपकरणों को दान में या सस्ती दरों पर देकर भारत ने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

दुनिया जानती है कि कोविड विषाणु से बचाव का स्थाई उपाय केवल टीका है। ऐसे में चीन व अन्य अमीर व शक्तिशाली देश टीके की आड़ में उपचार की पूरी कीमत वसूलने में लगे हैं। चीन ने तो हृदयहीनता का परिचय देते हुए बांग्लादेश से ड्रग ट्रायल के खर्च की भी मांग कर डाली थी। भारत भी ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने वैक्सीन के बहाने नाजायज प्रभाव जमाने की बजाय निस्वार्थ उदारता दिखाई और छोटे व बड़े देशों की समान रूप से मदद करने में लगा है। इसीलिए इसे टीका कूटनीति की बजाय टीका-मैत्री कहना कहीं ज्यादा उचित होगा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

आप के जिला अध्यक्ष बोले-प्रदेश में अपराधों पर नहीं लग पा रहा अंकुश

प्रयागराज । प्रदेश में अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लूट, हत्या, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। पुलिस के जवानों को भी अपराधी शिकार बना रहे हैं और इन अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। इससे प्रदेश की जनता परेशान है। यह बातें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने कहीं। उन्होंने कहा कि आए दिन व्यापारियों की हत्या और उनके रंगदारी के मामले भी सामने आते रहते हैं। जिला महासचिव सर्वेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया के हौसले बुलंद है, जिसका खामियाजा अब प्रदेश पुलिस को भी अपनी जान गवां कर उठाना पड़ रहा है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं रह गया है। आप की महिला जिला अध्यक्ष पूनम सिंह ने कहा कि आज महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार बनाने से पहले भाजपा ने कहा था कि वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाएगी, लेकिन सरकार बनाने के बाद भाजपा सरकार अपना वायदा भूल गई। आज महिलाएं भयभीत हें।

इन्होंने रखे अपने विचार- महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित महिलाएं थाने अपनी शिकायत दज कराने जाती हैं तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। उनकी सुनवाई नहीं होती। राष्ट्रीय परिषद् की सदस्य शिमलाश्री, जिला उपाध्यक्ष ललिता अग्रवाल, महिला जिला महासचिव सानिया मिर्जा, प्रदेश सचिव अंजली मिश्रा, गणेश चौरसिया, आरिफ खान, प्रदेश प्रवक्ता यूथ विंग सत्यम राय संघर्ष, प्रदेश सचिव सत्येंद्र तिवारी, जिला महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ट सद्दाम हुसैन, आरआर मिश्रा, डॉक्टर जावेद, हरेंद्र प्रताप ठाकुर, मोहम्मद जैद, जिला उपाध्यक्ष जेपी चौबे, मोहम्मद खालिद, शैलेन्द्र पाण्डेय, रमाकांत कश्यप आदि ने भी अपने विचार रखे।

कोसी नदी के गढ़ घाट पर नहीं बन सका पुल, नौका के सहारे 50 हजार लोग आते-जाते

खगडिया । आज भी फरकिया 'फरक'(अलग) ही है। अभी भी यहां के दर्जनों घाट-बाट दुरुस्त नहीं हुए हैं। जिसमें मुख्य रूप से कोसी नदी का गढ़ घाट शामिल है। दशकों से यहां पुल निर्माण को लेकर आंदोलन जारी है, परंतु अभी तक परिणाम ढाक का तीन पात ही निकला है। गढ़ घाट अलौली प्रखंड मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पुल बन जाने से तीन पंचायत चेराखेरा, आनंदपुर मारन और रामपुर अलौली के लोग सीधे प्रखंड मुख्यालय अलौली से जुड़ जाएंगे। हथवन पंचायत की ड्क्षबद टोली को भी नौका की सवारी से मुक्ति मिलेगी। 50 हजार से ऊपर की आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। फरकिया की आर्थिकी ही बदल जाएगी।

इन गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा- आनंदपुर, परास, गोला, हन्ना मुसहरी, श्याम घरारी, सिसवा, ड्क्षबद टोली, सोनमनकी, सुखासन, मारनडीह, मोहराघाट, भराठ, बोहरवा आदि।

कई दफा हुआ है आंदोलन- गढ़ घाट पर पुल निर्माण को लेकर कई बार आंदोलन हुआ है। मुख्य रूप से ये आंदोलन फरकिया मिशन की ओर से संचालित किया गया है। फरकिया मिशन के संस्थापक किरणदेव यादव कहते हैं- कोसी नदी की गढ़ घाट पर पुल बनने से फरकिया का कायाकल्प हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सांसद, विधायक और विधान पार्षद का घेराव करेंगे।

किसानों को मिलेगा लाभ- फरकिया में हजारों एकड़ में मक्का की खेती होती है। लेकिन आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसान औने-पौने दामों पर मक्का बेचने को विवश हो जाते हैं। क्योंकि नाव से मक्का लेकर अलौली आना हर किसान के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा एक कहावत है- फरकिया में आठ नदी बहती है। आठवीं नदी दूध की है। लेकिन आवागमन की असुविधा के कारण पशुपालकों को दूध की सही कीमत नहीं मिलती है। पास के किसान राजेश कुमार कहते हैं- हमलोग सोना(मक्का) उपजाते हैं और मिट्टी के भाव बेचते हैं। अगर गढ़ घाट पर पुल बन जाए, तो फरकिया की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी।

गढ़ घाट पर पुल को लेकर विधान सभा के आगामी सत्र में आवाज बुलंद करेंगे। इसको लेकर डीएम से भी मुलाकात की है। यहां पुल बनने से 50 हजार से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। किसानों को मक्का और दूध की सही कीमत मिलेगी। -रामवृक्ष सदा, विधायक, अलौली।

किसान की आत्महत्या मामले में बिजली विभाग ने झाड़ा पल्ला, कहा-दबाव का आरोप निराधार

सासाराम (रोहतास)। आर्थिक तंगी के कारण बिजली बिल नहीं चुका पाने और विभागीय दबाव के कारण किसान के आत्महत्या करने के मामले में बिजली विभाग ने पल्ला झाड़ लिया है। विभाग के ग्रामीण अंचल के अभियंता धर्मवीर ने इस मामले में बात रखी है। कहा है कि विभाग की ओर से किसी तरह की प्रताड़ना का आरोप पूरी तरह निराधार है।

जेई ने बताया कि नौगाई निवासी किसान दिनेश सिंह ने कृषि के नाम पर तीन फेज के तीन एचपी लाइन का कनेक्शन था। विभाग के रुपये बकाया था लेकिन इसके बावजूद उनका कनेक्शन नहीं काटा गया था। गत दिसंबर माह में किसान ने अपने कुल बकाया बिल के एवज में 20 हजार रुपये जमा किए थे। बकाया राशि जमा करने के लिए सिर्फ बिल से सूचना दी जा रही थी। किसान ने विगत 24 अक्टूबर 2019 को अधिक बिल होने के कारण जमा करने में असमर्थता जताते हुए आवेदन दिया था इस पर कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं इस संबंध में पूछने पर जेई ने कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। गौरतलब है कि आर्थिक तंगी से परेशान किसान दिनेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया गया कि बिजली का अधिक बिल आने के कारण वे परेशान थे। विभागीय दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इधर पिता के आत्महत्या के सदमे में एक पुत्री ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया था।

पाकिस्तान का बुरा हाल, डेढ़ साल से कर रहा भारत की समझौता एक्सप्रेस व मालगाड़ी का इस्तेमाल

अमृतसर । पाकिस्तान की बदहाली के बारे में तो पूरी दुनिया में चर्चाएं रही हैं, लेकिन उसकी हालत अब बदतर हो गई है। पाकिस्तान की कंगाली की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास ट्रेनों में लगाने के लिए बोगियां तक नहीं है। यही कारण है कि भारत की ट्रेन समझौता एक्सप्रेस और मालगाड़ी के 21 कोच पिछले डेढ़ साल से पाकिस्तन रेलवे उपयोग कर रहा है। भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से रिमाइंडर दिए जाने के बावजूद वह इन कोचों की लौटा नहीं रहा है। बता दें कि भारत और पाक के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 7 अगस्त, 2019 को आखिरी बार पाकिस्तान गई थी। 8 अगस्त, 2019 को समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान ने बंद कर दिया था। इस कारण इस ट्रेन के 11 कोच पाकिस्तान में फंस गए। इसके साथ ही भारत कि एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे भी पाकिस्तान में फंस गए थे। मालगाड़ी10 बोगियां में सामान लेकर पाकिस्तान गई थी। वह भी पाकिस्तान ने वापस नहीं भेजी हैं।पाकिस्तान से अपने कोच वापस लाने के लिए अटारी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की ओर से फिरोजपुर रेल डिवीजन को सूचित किया जा चुका हैं। डिवीजन स्तर पर रेलवे विभाग और मंलालय को भी इस संबंधी लिखकर भेजा जा चुका हैं।

भारतीय रेलवे की ओर से इन कोच को वापस लाने के लिए डेढ साल में दो बार पाकिस्तान रेलवे को रिमाइंडर भी दिए गए है, लेकिन उसके बाद भी इन कोचां की वापसी नहीं हो सकी। अटारी स्टेशन के सुपरिटेंडेंट अरविंद गुप्ता ने बताया कि ट्रेन रद होने के बाद से ही कोच पाकिस्तान में पड़े हुए हैं और वहीं पर प्रयोग हो रहे हैं। उनकी तरफ विभाग को लिखकर भेजा जा चुका हैं।

इस कारण बंद हुई ट्रेन - भारत सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस बंद करने का निर्णय लिया था। 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया था।

अमेठी में रेल ट्रैक पर मिला पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव, मृतक के भाई ने लगाया हत्या का आरोप

लखनऊ । अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे खनन घोटाले के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनके भतीजे शुभम (21) का शव आज अमेठी में रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद से जिले में सनसनी फैल गई है।

शुभम गायत्री प्रजापति के सबसे छोटे भाई जगदीश प्रजापति का सबसे छोटा बेटा था। शुभम पूर्व मंत्री के आवास विकास स्थिति आवास पर रहते थे। गुरुवार देर रात तक वह आवास नहीं गये थे। सूचना पर एसपी दिनेश सिंह सीओ अर्पित कपूर प्रभारी निरीक्षक श्यामसुंदर मौके पर पहुंचे जीआरपी प्रतापगढ़ ने शव को कब्जे में लिया है। घरवाले हत्या की आशंका जता रहे हैं।

अमेठी में शुक्रवार को सुबह रेलवे की पटरी पर गायत्री प्रसाद प्रजापति के 20 वर्षीय भतीजे का शव मिलने के बाद से जिले में खलबली मच गई है। इनके भतीजे का शव अमेठी के बारामासी खेरौना गांव में रेलवे ट्रैक पर मिला है।

अमेठी के थानाध्यक्ष श्याम सुंदर ने बताया कि शुभम (21) गुरुवार शाम को घर से बाहर निकला था। उसका शव शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। शव में सिर तथा धड़ अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि मामला रेलवे पुलिस का है, इसकी जांच जारी है।

गायत्री प्रजापति के छोटे भाई जगदीश प्रसाद प्रजापति का पुत्र शुभम चार भाइयों में सबसे छोटा था। परिजनों के मुताबिक गांव में दो लोगो के यहां कार्यक्रम थे 11 बजे रात तक वह वहां पर था। इसके बाद हम लोग यही सोचे कि वह आवास विकास स्थिति पूर्व मंत्री के आवास पर सोने चला गया है। शुभम के भाई अरुण प्रजापति ने आरोप लगाया कि मेरे बड़े पिता पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को विरोधी राजनीतिक साजिश के तहत परेशान कर रहे हैं। मेरे भाई को शराब पिलाकर पंचायत चुनाव की राजनीति में हत्या की गई है। अखिलेश यादव सरकार में परिवहन विभाग के बाद खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे अमेठी के गायत्री प्रसाद प्रजापति पॉक्सो तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में इन दिनों लखनऊ जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ खनन विभाग में कई करोड़ के घोटाले की जांच के साथ ही आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय भी इन दिनों गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ अघोषित संपत्ति की जांच कर रही है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिले गोरखपुर के सांसद रविकिशन, रेलवे के लिए मांगी जमीन

गोरखपुर । कैंट स्टेशन पर रास्ते के लिए सदर सांसद रवि किशन ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसद ने रक्षामंत्री से गोरखा रेजीमेंट डिपो (जीआरडी) की 7790 वर्ग मीटर भूमि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को हस्तांतरित करने की मांग की। जिससे यह रेलवे स्टेशन नेशनल हाईवे से सीधे जुड़ सके।

एम्स आने वाले मरीजों और यात्रियों की राह होगी आसान

सदर सांसद के अनुसार कैंट स्टेशन के नेशनल हाईवे से जुड़ जाने के बाद एम्स में आने वाले मरीजों और यात्रियों की राह आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आम यात्रियों को स्टेशन पर आवागमन करने के लिए रेलवे क्रासिंग पार करनी पड़ती है। क्रासिंग बंद होने पर यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाती है। स्टेशन के दक्षिण की तरफ मार्ग तैयार कर यात्रियों को सहूलियत दी जा सकती है। लेकिन दक्षिण की तरफ जीआरडी की भूमि है। यहां जान लें कि कैंट स्टेशन सैटेलाइट के रूप में विकसित हो रहा है। आम बजट में भी इस स्टेशन के विकास के लिए पर्याप्त धन मिला है। परंतु रास्ते की जमीन स्टेशन के समग्र विकास में राह का रोड़ा बना हुआ है।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कैंट स्टेशन के दक्षिण की तरफ दूसरा मार्ग तैयार करने के लिए फिर से कवायद शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने भूमि के बदले बगल में ही उतनी ही भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। रेलवे का कहना है कि स्टेशन के दक्षिण की तरफ सेना की भूमि होने के चलते दूसरा मार्ग तैयार नहीं हो पा रहा। अगर भूमि मिल जाए तो आम लोगों की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी।

केंद्र से लौटे अखिल कुमार को एडीजी गोरखपुर तथा भानु भास्कर को एडीजी कानपुर जोन का चार्ज

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद अपने मूल कैडर में वापस लौटे वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को तैनाती दी है। इसके साथ ही सात अफसरों का तबादला किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर के साथ ही कानपुर तथा आगरा जोन के एडीजी को भी बदला गया है। कासगंज कासजंग में पुलिस टीम पर हमले के बाद एडीजी आगरा जोन अजय आनंद को हटाया गया है।

केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद लौटते ही अखिल कुमार का गोरखपुर जोन के एडीजी पद पर तैनात किया गया है। लखनऊ के साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी रहे अखिल कुमार लम्बे समय तक एसटीएफ में रहे और फिर केंद्र सरकार की सेवा में चले गए। एसटीएफ में तैनाती के दौरान तेज तर्रार छवि के अफसर अखिल कुमार ने 2005 में बड़ा ऑपरेशन चलाकर चंबल के बीहड़ के शेर कहे जाने वाले दुर्दांत डकैत निर्भय गुज्जर का एनकाउंटर किया था। राष्ट्रपति के वीरता पदक से सम्मानित अखिल कुमार ने रणजी ट्राफी क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया है।

एडीजी गोरखपुर जोन के पद पर तैनात रहे दावा शेरपा को एडीजी सीबीसीआईडी के पद पर भेजा गया है। केंद्र सरकार में अपनी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद लौटे भानु भास्कर को एडीजी कानपुर जोन के पद पर तैनाती मिली है। कानपुर के बिकरू कांड के समय आइजी रहे एडीजी कानपुर जोन जेएन सिंह को एडीजी पीटीसी मुरादाबाद के पद पर भेजा गया है। कासगंज में कुख्यात अपराधी के हमले में एक सिपाही की मौत तथा दारोगा के गंभीर रूप से घायल होने के बाद आगरा के एडीजी अजय आनंद को हटाया गया है। एडीजी डॉ. बीआर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के पद पर तैनात रहे राजीव कृष्णा को आगरा जोन के एडीजी की जिम्मेदारी मिली है। अब तक आगरा जोन के एडीजी रहे अजय आनंद को एडीजी पीएसी, लखनऊ के पद पर तैनाती मिली है।

उत्तर प्रदेश का बजट होगा पेपरलेस, विधायक व एमएलसी की तीन दिनी ट्रेनिंग शुरू

लखनऊ । केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी पेपरलेस वर्क कल्चर की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2021-22 का बजट भी पेपरलेस पेश करने का फैसला किया है। सरकार ने इसकी जोरदार तैयारी भी कर ली है और पेपरलेस बजट में शामिल होने के लिए सभी विधायक व विधान परिषद सदस्यों को आइपैड के साथ बजट में शामिल होने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

विधान भवन में शुक्रवार से सभी पार्टी के साथ ही निर्दलीय विधायक व विधान परिषद सदस्यों का तीन दिनी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसका समापन रविवार को होगा। प्रशिक्षण के दौरान विधायक व विधान परिषद सदस्यों को हर रोज तीन-तीन घंटा आइपैड के उपयोग से बजट सत्र में शामिल होने की प्रक्रिया से पारंगत किया जाएगा। इन सभी को छह-छह के ग्रुप में तीन-तीन घंटा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश के वित्त तथा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की देखरेख में प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। भाजपा के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य छह-छह के ग्रुप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। तीन दिन तक तीन-तीन शिफ्टों में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में विधायकगण हिस्सा लेकर आइपैड चलाना सीख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के सभी मंत्री के साथ भाजपा के विधायक व विधान परिषद सदस्य भी आइपैड के प्रयोग में पारंगत होंगे। भाजपा विधायक तेजपाल नागर, कीरत सिंह, प्रमोद ऊंटवाल विक्रम सिंह सैनी तथा डॉ अनीता लोधी के साथ विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण लिया।

भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, कांग्रेस, एसबीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल व निषाद पार्टी के साथ निर्दलीय विधायक भी डिजिटल होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विधायकों के छह ग्रुप बनाए गए हैं। जिनके लिए प्रतिदिन दो शिफ्टों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पहली शिफ्ट सुबह 10ः30 बजे से 1ः30 बजे तक चलेगी तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 2ः30 बजे से शाम 5ः30 बजे तक चलेगी। इसके बाद भी इन सभी को कुछ अतिरिक्त समय दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से न सिर्फ प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है बल्कि सभी को एप्पल आइ पैड भी उपलब्ध कराया गया है।

गौरतलब है कि इस बार केंद्र में पेपर लेस बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में पेपर लेस बजट पेश करने की घोषणा की थी। जिसके बाद उन्होंने सभी विधायकों को 50 हजार तक की कीमत के आइ पैड का भी ऐलान किया था।

सीबीआइ ने फिर रोका लालू का रास्ता, नहीं मिली जमानत; हाई कोर्ट में अब अगले हफ्ते सुनवाई

रांची । चारा घोटाला में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों से कस्टडी की अवधि के सत्यापित आदेश की प्रति कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। लालू की ओर से जिस अवधि को कस्टडी में रहने का दावा किया जा रहा है। उसका सीबीआई विरोध कर रही है। इसीलिए अदालत ने उस अवधि से संबंधित निचली अदालत के आदेश की प्रति कोर्ट में सोमवार तक जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को निर्धारित की है।

लालू की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है। उन्होंने इस मामले में 42 माह जेल में बिताए हैं। सीबीआई ने इसका विरोध किया। कहा कि लालू प्रसाद यादव 37 महीना 6 दिन ही इस मामले में जेल में रहे हैं। अदालत में कस्टडी को लेकर दोनों के दावे के अंतर को देखते हुए मामले की सुनवाई अगले हफ्ते निर्धारित की है और दोनों से कस्टडी की सत्यापित प्रति अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से बीमारी और आधी सजा की अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए दुमका कोषागार मामले में जमानत देने की गुहार लगाई गई है। फिलहाल लालू के इलाज दिल्ली स्थित एम्स हो रहा है।

लालू को एकबार फिर झटका लगा है, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। सीबीआइ ने उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता शुक्रवार को एक बार फिर से रोक दिया है। लालू की जमानत पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और सीबीआई से उनके अबतक के कुल कस्टडी दिवसों की सत्यापित प्रति मांगी है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि लालू को आज जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव के अनुसार दुमका वाले मामले में वे 42 माह जेल में रहे। जबकि सीबीआई के अनुसार 37 माह 6 दिन। इस पर कोर्ट ने दोनों से कस्टडी के दिनों में होने वाले अंतर की सत्यापित आदेश

की प्रति कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है।

झारखंड हाईकोर्ट में लालू की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल सुनवाई में शामिल हुए। लालू के मामले की हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने दावा किया कि आज लालू यादव को जमानत मिल जाएगी और वे जेल से बाहर आ जाएंगे। बताया गया कि लालू प्रसाद ने 8 फरवरी को सजा की आधी अवधि 42 माह 13 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी आधार पर उच्च न्यायालय से जमानत की मांग की गई है। इधर सीबीआइ ने लालू की जमानत का पुरजोर विरोध किया है।

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को अदालत से सात साल की सजा मिली है।

अगर लालू प्रसाद यादव को अदालत से जमानत मिलती तो वे जेल से बाहर आ जाते। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। जबकि डोरंडा कोषागार वाले मामले अभी सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में सजा की अवधि पूरा कर चुके है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सीबीआइ इसका विरोध कर रही है। बता दें कि लालू प्रसाद का अभी दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन रहा। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन राहत नहीं मिल सकी। बेल मिलने पर लालू जेल से बाहर आ जाते, क्योंकि पहले ही उन्हें तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। वे चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता हैं। सजा काटने के लिए उन्हें रांची के बिरसा मुंडा जेल भेजा गया है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित की गई थी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद प्रमुख लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।

सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव ने हाई कोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी रांची की सीबीआइ स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

बारा नरसंहार: बिहार के गया में 29 साल पहले उग्रवादियों ने रेता था 35 लोगों का गला, घटना याद कर सिहर उठते हैं लोग

गया । बात आज से लगभग तीन दशक पूर्व 12 फरवरी 1992 की है। गया जिले के टिकारी प्रखंड के बारा गांव में नक्सली संगठन एमसीसी के सैकड़ों हथियारबंद उग्रवादियों ने गांव पर हमला कर एक हीं जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। कहने को तो घटना के करीब तीन दशक गुजर गए परंतु जख्म अभी भरे नहीं हैं। पीड़ितों के जेहन में भय व दुख-दर्द आज भी ताजा हैं। समय ने आग पर राख की एक परत डाल दी है, परंतु दर्द की चिंगारी अब भी अंदर सुलग रही है।

घटना के बाद तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों के आश्रितों को नौकरियां देकर मरहम लगाने का प्रयास किया था। परंतु उन पीड़ितों में 11 परिवार ऐसे बदकिस्मत हैं जिन्हें वह लाभ आज तक नहीं मिल सका है। जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण केवल उनके लिए वादों की खेती करते रहे हैं, जिनसे अब तक केवल निराशा, तनाव और अवसाद जैसी फसलें हीं उपजती रही हैं। नरसंहार में मारे गए बारा गांव के हरिद्वार सिंह, भुषाल सिंह, सदन सिंह, भुनेष्वर सिंह, संजय सिहं, शिवजनम सिंह, गोरा सिंह, बली शर्मा, आशु सिंह तथा भोजपुर जिला अकबारी गांव के श्रीराम सिंह एवं परैया थाना राजाहरी गांव के प्रमोद सिंह के आश्रित अब भी नौकरी की आस लगाए बैठें हैं। सरकार की दोरंगी नीति के शिकार ये पीड़त अब भी उम्मीदों के डोर थामें है कि शायद हुक्मरानों को तरस आ जाए और उनकी किस्मत पलटी खा ले।

नरसंहार की पीड़ा से कम नहीं है सरकार की उपेक्षा- पूर्व सरपंच व वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मदन सिंह कहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद आश्रितों को नौकरी नहीं दिया जाना नरसंहार में मिली पीड़ा से कम दुखदायी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सीपी ठाकुर ने वर्तमान सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में कारवाई करने को कहा था। परंतु उसे भी अनसुना कर दिया गया। जबकि उनके पत्र के आधार पर स्थानीय डीएसपी ने एक जांच प्रतिवेदन भी सरकार को भेजा था। नरसंहार की घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संपर्क पथ का निर्माण, स्थायी पुलिस चौकी, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा बिजली, सिंचाई, पेयजल आदि सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणाएं आज तक पूरी तरह पूर्ण नहीं हो सकीं। सड़क बनी लेकिन अधूरी है।

चौकी के लिए ग्रामीण श्लोक सिंह जमीन दान में दे दी, लेकिन चौकी नही बनी। स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू तो कर दिया गया है, लेकिन पद सृजन आज तक नहीं हुआ है। इतने वर्षों में वे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नही कराई जा सकी हैं, जो कि एक सामान्य गांव में भी हो जानी चाहिए थी।

विवादित निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी अपहरण के मामले में भगोड़ा घोषित, कुर्क होगी संपत्ति

लखनऊ । विवादों में रहने वाले महराजगंज जिले के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी एक बार फिर से चर्चा में हैं। अपहरण के एक मामले में कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी को फरार घोषित करने के साथ ही वारंट भी जारी किया है।

पत्नी सारा की हत्या के आरोप में सीबीआइ की जांच झेल रही अमन मणि को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने तथा पुलिस से उलझने के कारण करीब छह महीना पहले उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया था। अब वह फिर नये विवाद में हैं। लखनऊ में कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में पत्नी सहित आजीवन कारावास की सजा झेल रही पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के विधायक पुत्र अमनमणि भी उनकी राह पर हैं।

अपहरण के एक मामले में कई वारंट के बाद भी पेश न होने वाले निर्दलीय विधायक अमन मणि को एमपी/एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। विशेष न्यायाधीश पीके राय ने भी मामले में अमन मणि की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ फिरौती के लिए गोरखपुर के एक व्यापारी के अपहरण का मामला दर्ज है। केस लखनऊ के गौतमपल्ली थाना में दर्ज है। आरोप है अमन मणि त्रिपाठी ने अपने कुछ साथियों के साथ गोरखपुर के व्यापारी ऋषि पाण्डेय का लखनऊ से अपहरण कर लिया था। इस दौरान व्यापारी के साथ रास्ते में मारपीट की गई। अमन मणि पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारी को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अमनमणि और उसके साथियों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में छह अगस्त 2014 को मामला दर्ज किया गया था।

व्यापारी के अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में लखनऊ की पुलिस ने अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ 28 जुलाई 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीखों पर अमनमणि की तरफ से बीमारी का हवाला देकर लगातार हाजिरी माफी की अर्जी लगाई जा रही थी। जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए अमन मणि को भगोड़ा घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अमन मणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र हैं। अमरमणि त्रिपाठी लखनऊ में 2003 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में गोरखपुर जेल में पत्नी के साथ उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

वाम मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन, सूबे की सियासत में वामपंथियों के संगठन की प्रासंगिकता कायम

कोलकाता । बंगाल में 34 वर्षों तक शासन करने वाले वामपंथी दल वर्तमान में अस्तित्व रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वाममोर्चा (वामो) के छात्र और युवा संगठनों ने बेरोजगारी समेत कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर गुरुवार को राज्य सचिवालय (नवान्न) अभियान करने की कोशिश कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरीकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करने के साथ उन पर जमकर लाठियां भांजी।

वाम मोर्चा के नेताओं ने दावा किया कि उनके सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए हैं और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को 12 घंटे का बंगाल बंद आहूत करने की घोषणा की है। वामपंथी युवा व छात्र संगठन के सदस्यों का जुलूस कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे धर्मतल्ला में एसएन बनर्जी रोड पर रोक दिया। वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जब बैरीकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वामपंथी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने बैरीकेड पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प में कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे।

दरअसल वामपंथियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि आज भी उनके संगठन की सूबे की सियासत में प्रासंगिकता है। यहां यह जानना आवश्यक है कि बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस की हालत दयनीय है। यही वजह है कि दोनों गठबंधन कर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही नहीं, अपनी पूरी शक्ति दिखाने के लिए इसी माह 28 फरवरी को ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में संयुक्त रैली आयोजित कर लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि तृणमूल और भाजपा का विकल्प वाम मोर्चा और कांग्रेस ही हैं।

इससे पहले उन्होंने नवान्न अभियान से लोगों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। शुक्रवार को बंगाल बंद आहूत करना भी वामपंथियों की रणनीति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बंगाल में थे और इस समय सूबे की सियासत में सीधी लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच चल रही है। यहां तक कि मीडिया में भी तृणमूल और भाजपा की सियासी गतिविधियां ही सुर्खियां बन रही हैं। ऐसे में वाम मोर्चा के लिए यह अभियान सुर्खियां बटोरने वाला साबित हुआ, क्योंकि बंगाल की स्थानीय मीडिया में नवान्न अभियान भी अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम के साथ प्रमुखता से छाया रहा।

नादिया में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान के तहत कार्यकर्ता एक दीवार को पेंट हुआ ।

राजपत्रित अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी से की मुलाकात

भोपाल। मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव से मुलाकात की गई। मुख्य सचिव को बताया गया कि विभिन्न विभागों में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों को नियमानुसार आईएएस अवार्ड किया जावे, शीघ्र पदोन्नतियाँ प्रारंभ की जावें,वास्तविक वेतन वृद्धि के साथ रोके गए समस्त डीए दिए जावें। विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगति दूर की हो। तकनीकी शिक्षा में सातवां एआईसीटीई वेतन दिया जरूरी है। 300 दिन का अर्जित अवकाश का लाभ दिए जाने हेतु 1991 का फार्मूला हटाया जाये। वरिष्ठता के आधार पर ही प्रभारी अधिकारी बनाया जावे। सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के पीपीओ शीघ्र जारी हों। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद नाम तथा ऊर्जा विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता दी जावे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विभागीय गठित मिश्रा समिति की अनुशंसा लागू करने एवं सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर हो। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ दिया भी आश्यक है। अधिवार्षिकी आयु 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र के समान की जावेए प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 5 स्तरीय उच्चतर पदोन्नत वेतनमान सातवें वेतनमान की भांति एचआरए एवं अन्य भत्ते जैसी मांगों पर विस्तार के साथ चर्चा हुई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डीएके यादव ने कहा कि मुख्य सचिव ने शीघ्र ही मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया है।

सेवानिवृत्ति पर दी विदाई

राजधानी भोपाल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल की प्रोफेसर डॉ पदमा श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें महाविद्यालय परिवार की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। डॉ पदमा श्रीवास्तव महाविद्यालय में विगत 21 वर्षों अपनी सेवाएं दे रही थीं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ मथुरा प्रसाद ने शाल श्रीफल एवं पौधा भेंट कर उन्हें स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया।

वृद्धाश्रम में वरिष्ठजनों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

भोपाल । मध्य प्रदेश रेडक्रॉस ने अभिनव पहल करते हुए गुरुवार को भोपाल शहर के दो वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों के लिये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। रेडक्रॉस अस्पताल के 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इन दोनों संस्थाओं में रह रहे वरिष्ठजनों का हेल्थ चैक अप किया, फिर जांच के लिये सेंपल लिए और निशुल्क दवाएं भी दी गई। रेडक्रॉस मध्य प्रदेश और रेडक्रॉस अस्पताल की टीम चूना भट्टी स्थित लायंस क्लब वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठजनों का स्वास्थ्य परीक्षण सुबह 10 बजे से शुरु किया। शिविर में बुजुर्गों का वजन चैक करने के बाद बीपी और अन्य जांच की गई। अधिकतर लोगों को जोड़ों की समस्या देखने को मिली। कुछ लोगों को मौसमी बीमारियों की शिकायत भी थी। रेडक्रॉस की टीम की इस पहल से वरिष्ठजनों के चहरे खिल गए। रेडक्रॉस के चैयरमेन आशुतोष पुरोहित से लाइंस क्लब वृद्धाश्रम में रह रही एम. एलिज़ाबेथ और उनके पति एम. गनगन्ना ने मुलाकात की। रेड क्रॉस की जनरल सेक्रेटरी डॉ.प्रार्थना जोशी ने बताया कि टीम में छह अलग-अलग विशेषज्ञ डॉक्टर, जिनमें डॉ. आनंद जाट (एमडी), डॉ. जेपी बुच (ईएनटी), डॉ. प्रेरणा थापा (स्त्री रोग), डॉ. भारती सोनी (आंख), डॉ. ऋचा रूपला (चर्म रोग), डॉ. दिव्या (ऑर्थो) मौजूद थे। डॉक्टर्स के अलावा टीम में मेडिकल ऑफिसर, पैथोलोजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, अटेंडर और रेडक्रॉस एमपी शाखा के कर्मचारी भी मौजूद थे। रेडक्रॉस ने शहर के दोनों वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी लेते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। अब इन संस्थानों में हर माह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा।

अधिकारियों से नहीं बात, हड़ताल पर गए तो होगी कड़ी कार्रवाई

भोपाल एजेंसी । सहकारिता विभाग के आला अधिकारी और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पीड़ित जनता की सेवा करने वाले गरीब कर्मचारी आमने सामने देख रहे हैं। किसानों के साथ जनता को खाद बीज एवं राशन समय पर उपलब्ध कराने वाले फील्ड सेवकों की मंगलवार के बाद बुधवार को पहले अपेक्स बैंक और उसके बाद विंध्यांचल में विभाग के आला अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी। पर दुर्भाग्य रहा कि वार्ता बेनतीजा रही है। सहकारिता विभाग कमिश्नर ने कहा कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो फिर कार्यवाही की जाएगी।

बताना होगा कि उचित मूल्य की दुकानों में तैनात कर्मचारी पिछले 1 सप्ताह से समान कार्य समान वेतन मान की मांग कर रहे हैं। इस मांग के साथ साथ इनका विरोध राशन आवंटन में कटौती को लेकर भी है। इनका कहना है कि उच्च स्तर से राशन कटौती के आदेश जारी किए जा रहे हैं जबकि फील्ड में जनता के कोपभाजन का शिकार उन्हें होना पड़ रहा है। इसी तारतम्य में नरेश पाल आयुक्त एवं पंजीयक सहकरिता अरविंद सेंगर अपर आयुक्त सहकारिता प्रदीप नीखरा मैनेजिंग डायरेक्टर अपेक्स बैंक भोपाल के साथ संयुक्त कमेटी की दो दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन विफ ल रही है। कमेटी द्वारा शासकीय कर्मचारीयो की भाँति वेतन एवं अन्य सुविधाएं की मांग उच्चाधिकारियों के सामने रखी गई। किन्तु सहमति आशा अनुरूप नही बन पाई। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बीएस चौहान का कहना है कि सिस्टम अब विश्वास की गवाही नहीं दे रहा है। हमें भरोसा था कि प्रदेश में हजारों वह गरीब कर्मचारी आज न्याय पा सकेंगे लेकिन हमारे साथ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धोखा किया जा रहा है। चौहान का कहना है कि बुधवार को फिर विंध्याचल भवन में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उम्मीद थी कि इस बैठक में कुछ न्याय के रास्ते खुलेंगे। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा आंदोलन को लेकर नाराज रवैया अपनाया गया। यह तक कहा गया गया कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो कार्यवाही की जाएगी। विभाग से बात नहीं बनने के कारण कर्मचारियों ने साफ कहा है कि प्रदेश भर में 18 फरवरी को सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे।

सहकारिता कर्मचारियों ने कहा 18 फरवरी को देंगे सामूहिक इस्तीफे

इनका कहना :-

हमारे आंदोलन को अधिकारियों द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी एक प्रकार से मांगों का समाधान करने की बजाय मनमाना रवैया अपना रहे हैं। अब 18 फरवरी को प्रदेश भर मे सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे।

ओपी गोस्वामी, संरक्षक, मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी संघ

हमारे सरकार से वार्ता के सभी प्रयास विफल हो हो गये हैं। विभाग द्वारा न तो मांगों के समाधान का रास्ता निकाला जा रहा है। न ही आगे इनका कोई रूख दिख रहा है। अब सामूहिक इस्तीफे ही एकमात्र विकल्प है।

लखन यादव, पदाधिकारी, सहकारिता समिति कर्मचारी संघ

प्रदेश में सहकारिता कर्मचारी अब अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। अधिकारी हमारे आंदोलन को कुलचने की लाख कोशिश करें, लेकिन हम अपने साथियों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे।

कुंवर बीएस चौहान, अध्यक्ष, मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी संघ

13 को होगा बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन

भोपाल। दि बुध्दिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 13 फरवरी को तुलसी नगर स्थित करुणा बुध्द विहार भोपाल के प्रांगण में बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पधारने वाले अधिकांश युवक युवतियों का संबंध तय होने में सफलता प्राप्त हो रही है। वर्तमान में काफी संख्या में विभिन्न शासकीय कार्यालयों में सेवारत, निजी व्यवसाय करनेवाले, विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में सेवारत डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर कार्यरत विवाह योग्य युवक युवतियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

संतजन परमार्थ सोसाइटी की चेतावनी सरकार में 20 फ़ीसदी आरक्षण मिले

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय संत जन परमार्थ सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 31 बिंदुओं की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राम गिरि जी महाराज ने सरकार को इसके समाधान के लिए 3 दिन का समय दिया। मांगों में जैसे सरकार में संत जनों को 20 फ़ीसदी आरक्षण ,मंदिरों के लिए मुफ्त बिजली के अलावा ऋण पुस्तिका देने की मांग की गई है। ताकि बाउंड वाले केस में वे इसका इस्तेमाल कर सके। मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है । महंत राम गिरि जी महाराज डंडा वाले ने दावा किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ संत जनों को नहीं मिलता है इसलिए हमें भी उसमें शामिल किया जाए । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुजारी कुटीर बनाने की स्कीम दी जाए । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक स्थानों को टारगेट करके उन्हें गिरा रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने भोपाल के मनभावन टेकरी के बारे में बताया। पुजारी के मानदेय बढ़ाने की भी उन्होंने मांग रखी है महंत राम गिरी जी महाराज ने दावा किया कि अपनी मांगों को लेकर धार्मिक राजस्व मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं ऐसे धार्मिक स्थल 10 साल हो गए हैं उनका मालिकाना हक दिया जाए गौशालाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने सरकारी कर्मचारियों की जांच के बाद नियुक्ति की जाए।

वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू मठ मंदिर बोर्ड गठन की मांग

6 लाख 80 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड के साथ भोपाल प्रदेश में दूसरे स्थान पर

भोपाल। आयुष्मान भारत निरामय योजना मध्यप्रदेश के तहत भोपाल जिले में अभी तक 6 लाख 80 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और भोपाल जिला देश में दूसरे स्थान पर है। जिले में पात्र हितग्रहियों को जोड़ने के लिये अभियान जारी है। आयुष्मान योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए जिले के शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत संबल योजना, खाद्य पर्ची धारक, एसईसीसी डाटा अंतर्गत पात्र परिवार आयुष्मान योजना के अंतर्गत सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पात्र परिवार प्रति वर्ष सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में कोरोना, कैंसर आदि जैसे गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सके गा। अधिक जानकारी के लिए 1800-233-2085 या 14555 पर कॉल कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कोविड का इलाज भी कराया जा सकता है।योजना के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में इलाज करवाने पर 60 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार उठाती है। वहीं निजी चिकित्सालयों में इलाज पर शत.प्रतिशत भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।

महाराष्ट्र के यवतमाल में 20 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत

नागपुर । संयुक्ता किसान मोर्चा के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत 20 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में किसान महापंचायत और एक सार्वजनिक रैली करेंगे। बता दें कि संयुक्ता किसान मोर्चा के अंतर्गत 40 किसान यूनियन आती हैं जो दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महाराष्ट्र को-ऑर्डिनेटर संदीप गिद्दे ने गुरुवार को बताया कि टिकैत, युदवीर सिंह और एसकेएम के कई अन्य नेता 20 फरवरी को यवतमाल शहर के आजाद मैदान में किसान महापंचायत और जनसभा करेंगे।

संदीप गिद्दे ने कहा, टिकैत महाराष्ट्र में किसान महापंचायत की शुरुआत यवतमाल से करना चाहते हैं, किसानों की आत्महत्या की सर्वाधिक घटनायें यहीं से सामने आयी हैं। विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ भागों से किसान महापंचायत में भाग लेने की इच्छुक हैं, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों से अनुमति मांगी है। यवतमाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान महापंचायत आयोजकों ने भी आयोजन के लिए अनुमति मांगी है।

गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 79 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के सिंघु, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। जबकि नाराज किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि बिल वापसी तक ये आंदोलन चलेगा। बता दें कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलने की बात पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकेट पर जमकर निशाना साधा।

चढ़ूनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे बयानों से हंसी आती है कि किस परिवेश में उन्होंने (राकेश टिकैत) ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि आंदोलन 2 अक्टूबर तक कैसे चल सकता है बल्कि जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 2 अक्टूबर वाली बात राकेश टिकैत का निजी बयान है किसी संगठन का नहीं।

उदयपुर जिले के रोबिया गांव में चार माह से लापता परिवार के मुखिया का शव उसी के घर में दफन मिला, परिजनों का नहीं लगा पता

उदयपुर । जिले के रोबिया गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। चार माह से लापता परिवार के मुखिया का शव उसी के सूने मकान में दफन मिला, जबकि परिवार के अन्य सात सदस्यों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव निकाला तो पता चला कि हत्या के बाद उसका शव गाड़ दिया गया। शव के गले में रस्सी बंधी हुई थी। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि रोबिया गांव में भगु अहारी अपनी पत्नी और छह बच्चों के साथ केलूपोश मकान में रहता था। दीपावली के बाद से परिवार के सभी सदस्य लापता हो गए। लोगों को लगता था कि गांव के कई परिवार मजदूरी के लिए गुजरात जाते हैं और भगु अहारी भी संभवतः मजदूरी के लिए परिवार सहित गुजरात चला गया होगा। किन्तु भगु तथा परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल बंद आने पर उसके छोटे भाई रहेश अहारी ने परिवार के सदस्यों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

रमेश ट्रक चालक है तथा महीनों तक गांव नहीं लौटता। गत मंगलवार की रात वह लंबे समय बाद गांव लौटा था। इस बीच वह अपने बड़े भाई की तलाश में गांव से एक किलोमीटर दूर उनके केलुपोश मकान पर पहुंचा तो उसने मकान के आंगन की मिट्टी उभरी हुई देखी। जिस पर उसे शंका हुई और पुलिस को सूचित किया। खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा एफएसएल टीम को बुलाया गया। संदिग्ध जगह पर खुदाई कराई गई तो उसमें एक शव निकला, जिसकी पहचान भगु अहारी के रूप में की गई। प्लास्टिक के कट्टे में बांधा हुए शव के गले में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसकी मौत लगभग चार महीने पहले गला घोंटने से हुई थी। हत्यारों ने वारदात के बाद उसका शव उसी के मकान के आंगन में दफना दिया पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इसी के साथ एक बार फिर भगु के लापता परिवार के सदस्यों की तलाश भी शुरू की गई है। शुक्रवार को पुलिस का एक दल गुजरात भेजा गया है, जहां उनके मजदूरी किए जाने की उम्मीद की जा रही है। इधर, सभी परिजनों के मोबाइल फोन बंद होने से किसी अनहोनी की आशंका ग्रामीण जता रहे हैं।

महाराष्ट्र के सोलापुर में एसयूवी और ट्रक की भीषण टक्कर, चार की मौत; दो घायल

पुणे । महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शुक्रवार सुबह 6 बजे एसयूवी और ट्रक की भीषण टक्कर में एक लड़की समेत चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये दुर्घटना सांगोला-पंढरपुर के कसेगांव के पास हुई थी। घायलों में से एक की हालत काफी गंभीर बतायी गई है।

पंढरपुर तहसील पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर किरण अवचर ने कहा, मृतक और घायल कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ तहसील के रहने वाले थे। वे पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के दर्शन करने जा रहे थे।÷ मिली जानकारी के अनुसार एसयूवी में कुल 16 लोग सवार थे।

इस हादसे में एक व्यक्ति, दो महिलाओं और एक लड़की की मौत हो गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने कहा कि एसयूवी के चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह सड़क के किनारे खड़े स्थिर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी को कटर से काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। हादसों में मृतकों के शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मृतकों की शवों और घायलों को उप-जिला अस्पताल में भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि बीती 23 जनवरी को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक वाहन के 150 गहरी खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई थी और सात लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 10.30 बजे तोरणम हिल स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित खाकी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। सभी पीड़ित नंदुरबार के झप्पी फलाई गांव के निवासी थे। ये लोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी के लिए वाहन से तोरणमल जा रहे थे। चालक का वाहन से नियंत्रण खो जाने के कारण वाहन 150 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा।

चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने सौंपी स्टार प्रचारकों की सूची, कई बड़े नाम शामिल

अहमदाबाद । केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तथा ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा सांसद संजय सिंह आप के स्टार प्रचारक होंगे। राज्य चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी गई जिसमें राष्ट्रीय व प्रदेश के नेताओं के नाम शामिल हैं। भाजपा ने अपने बीच नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटील तथा ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर आदि नेताओं के नाम शामिल है।

ठाकुर प्रदेश की राजनीति में पिछले काफी समय से बैकफुट पर थे। विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद से ठाकुर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चले गए थे। गत दिनों गुजरात के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह भी अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए अल्पेश ठाकोर को वापस कांग्रेस में ला सकती है। गत विधानसभा चुनाव में अल्पेश ठाकुर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल तथा दलित नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिग्नेश मेवानी की तिकड़ी ने भाजपा को घेर कर रखा था।

कांग्रेस को इन युवा नेताओं के आंदोलन का खासा फायदा भी हुआ तथा कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 79 सीटों तक पहुंच गई थी। कांग्रेस इस चुनाव में भाजपा से महज 20 सीट जबकि विधानसभा में बहुमत से महज 13 सीट ही दूर रह गई थी। भाजपा इस चुनावी गणित को बहुत अच्छी तरह समझती है तथा विधानसभा उपचुनाव में हार के बावजूद अल्पेश ठाकुर को एक बार फिर शहरी तथा ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए अपना स्टार प्रचारक चुनाव ताकि आगामी विधानसभा चुनाव तक उसकी मतदाताओं में पैठ का पार्टी के पक्ष में उपयोग किया जा सके।

आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी ने भी राज्य के चुनाव आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित पार्टी के 8 विधायकों के नाम शामिल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की कमान गोपाल इटालिया संभाल रहे हैं जबकि मीडिया प्रभारी तुली बैनर्जी को बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव कि पिछले कुछ साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी तथा सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवारों की सूची जारी कर इस चुनाव में प्रत्याशी उतारने की पहल की है।

उधर एआईएमआईएम के लेता असदुद्दीन ओवैसी तथा इसके गठबंधन में शामिल भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता छोटू भाई वसावा स्टार प्रचारक के रूप में देखे जा रहे हैं।

दीपिका पादुकोण

ने कई बड़े स्टार्स को पछाड़ा, 'सेलेब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी' में हासिल किया ये स्थान

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी शानदार एक्टिंग के लिए फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं। अब डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी 'सेलेब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2020' में दीपिका को फिर से मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलेब के खिताब से नवाज़ा गया है। बता दें, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की टोटल ब्रांड वैल्यू 50.4 मिलियन डॉलर है। इस लिस्ट में दीपिका के बाद अभिनेत्री आलिया भट्ट 48.0 मिलियन ब्रांड वैल्यू के साथ मोस्ट फीमेल वैल्यूएबल सेलेब्रिटी में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं दीपिका और आलिया की ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी में वैल्यू सलमान खान से भी ज्यादा है।

आपको बता दें कि टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने दीपिका पादुकोण को साल 2019 में सबसे भरोसेमंद फीमेल सेलेब्रिटी की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा था। वहीं, दीपिका पादुकोण की सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 52 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 30 मियिलन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली 237.7 ब्रांड वैल्यू के साथ पहले स्थान पर हैं। इस सूची में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टारों को पछाड़ दिया है।

वहीं अगर बात उनके वर्कफ्रंट की करें तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस साल बैक टू बैक कई फिल्मों में नज़र आने वाली हैं। इस वक्त वो अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी आगामी फिल्म 'पठान' की शूटिंग कर रही हैं। इसके अलावा अभिनेता अपने पति रणवीर सिंह के साथ फिल्म '83' में जल्द ही नज़र आएंगी।

ये फिल्म 1983 विश्वकप विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की बायोपिक है। इसमें दीपिका कपिल देव की पत्नी रोमी देवी का किरदार निभा रही हैं, वहीं इस फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही दीपिका शुकन बत्रा की अनटाइटल फिल्म में भी अहम रोल प्ले कर रही हैं।

अनीता हसनंदानी

के घर आया नन्हा मेहमान, बेबी ब्वॉय को दिया जन्म

टीवी इंडस्ट्री के फैन्स के लिए खुशखबरी है। एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने बेटे को जन्म दिया है। पति रोहित रेड्डी संग इन्होंने पहले बेबी का वेलकम किया है। रोहित रेड्डी ने यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर सभी को खुशखबरी दी। बता दें कि अनीता हसनंदानी 'नागिन' में नजर आई थीं, जहां से उन्हें फेम मिली।

सोशल मीडिया पर न्यूज शेयर करते हुए रोहित रेड्डी ने लिखा, "ओह ब्वॉय!" इसके साथ ही फोटो में आप देख सकते हैं कि रोहित, अनीता के गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं और अनीता बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। साथ ही तारीख लिखी है, 9 फरवरी, 2021।

कुछ समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में अनीता हसनंदानी ने बताया था कि मैं पूरी तरह से बेबी के लिए तैयार हूं। हमने हाल ही में बेबी के लिए एक स्पेशल क्रिब खरीदा है और उसे सेट किया है। मैंने कई फोटोशूट्स किए हैं, लेकिन कोई प्रेग्नेंसी पीरियड में किए जाने वाले फोटोशूट से उनकी तुलना नहीं कर सकता है। मैटरनिटी शूट में मैंने सबसे ज्यादा मजे किए हैं। एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि वह फरवरी के महीने में बेबी को जन्म देंगी।

इसके साथ ही अनीता ने बताया था कि वह खुद को प्रेग्नेंसी पीरियड में शांत और खुश कैसे रख रही हैं। योग करने के साथ वह अपने डॉगी संग खेलती हैं। खुद के साथ क्वॉलिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि प्रेग्नेंसी पीरियज में वह खुश रहें। अब जब अनीता और रोहित नए मेहमान के आने को लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं फैन्स और टीवी सेलेब्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।

काले हिरण शिकार केस में सलमान खान ने कोर्ट में दिया था झूठा हलफ़नामा, 18 सालों बाद अब मांगी माफी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर चल रहे काले हिरण के शिकार केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले पर बीते मंगलवार को सलमान ने झूठा हलफ़नामा जमा कराने के लिए माफी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने माना है कि ये सब गलती से हुआ है. वहीं ये हलफ़नामा उन्होंने 18 साल पहले यानी 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट के सामने पेश किया था। इस केस पर 1998 से सुनवाई जारी है, वहीं गुरुवार 11 फरवरी को इस मामले में आखिरी फैसला भी आने वाला है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों का शिकार किया था।

इस केस में सुनवाई का सिलसिला पिछले दो दशकों से जारी है, वहीं अब ये मामला अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो हाल ही में सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा है कि 8 अगस्त 2003 में गलती से कोर्ट को फर्जी एफिडेविट जमा कराए दिए गए थे। उनका कहना है कि 'सलमान व्यस्त होने की वजह से भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए गया है और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि उनका लाइसेंस मिल नहीं रहा है।

इसके साथ ही सलमान के वकील ने अपील की है कि इसके लिए सलमान खान को माफ कर दिया जाना चाहिए। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक गांव में काले हिरणों का शिकार किया था। जिसकी वजह से आर्म एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हुआ था और कोर्ट ने उन्हें अपने हथियार का लाइसेंस जमा करने के लिए कहा था।

उस दौरान सलमान खान ने कोर्ट में हलफ़नामा देते हुए बताया था कि उनका लाइसेंस खो गया था। इस मामले को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में स्न्ढ्ढक्रभी दर्ज करवाई गई थी। वहीं अब देखना होगा कि सलमान खान की इस माफी पर कोर्ट का क्या फैसला है।

प्रियंका चोपड़ा

ने अलमारी में छुपाया अपना बॉयफ्रेंड, जब आंटी ने पकड़ा तो मच गया हंगामा

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने आने वाले संस्मरण अनफिनिश्ड को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रियंका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े ये किस्से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। वहीं हाल ही में उनकी की लव लाइफ से जुड़ा एक वाकया जबरदस्त सुर्खियों में है। जिसमें प्रियंका को अपने बॉयफ्रेंड को एक आलमारी में छुपाना पड़ा था। लेकिन उनकी आंटी ने उन्हें पकड़ लिया था, इसके बाद जो हुआ वो किसी टीनएजर के लिए डरावने सपने से कम नहीं है।

प्रियंका चोपड़ा ने अपने संस्मरण अनफिनिश्ड को बीते मंगलवार यानी 9 फरवरी को रिलीज कर दिया है। इस किताब में प्रियंका ने बताया कि उन्होंने टीनएज में अपने कुछ साल अमेरिका में बिताए थे, तब वो अपने रिश्तेदार के पर रहती थीं और वहीं स्कूल भी जाती थीं। इसी दौरान वो स्कूल में बॉब नाम के एक लड़के के प्यार में पड़ गई थीं। जूम की एक रिपोर्ट की मानें तो इसके कारण मुश्किल में फंस गई थीं।

प्रियंका ने बताया कि जब वो 10वीं क्लास में थीं तो वो अपनी एक किरण नाम की आंटी के साथ इंडिआनापलिस में रहती थीं। वहीं वो अपने स्कूल में बॉब नाम के एक लड़के से मिलीं, जिसने अपने फनी और रोमांटिक अंदाज से उनका दिल जीत लिया। प्रियंका पूरी तरह प्यार में डूबी थीं। यहां तक कि दोनों ने शादी की भी प्लानिंग कर ली थी।

प्रिंयका ने बताया कि एक दिन वो बॉब के साथ टीवी देख रही थीं, तभी उनकी किरण आंटी घर आ गईं। ये उनके घर आने का वक्त नहीं था। ये देखकर हड़बड़ाई प्रियंका ने बॉयफ्रेंड को अपने कमरे में लेजाकर अलमारी में बंद कर दिया। वहीं उनकी आंटी को शक हो चुका था और आते ही उन्होंने गुस्से में प्रियंका से अलमारी खोलने के लिए कहा। बॉब को प्रियंका की अलमारी में पाकर उनकी आंटी बहुत नाराज हुईं और उनकी मां से शिकायत भी कर दी। बताया जाता है कि इसके कुछ समय बाद ही प्रियंका भारत वापस आ गई थीं.

भारत-इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से

8 साल से घर में लगातार दो टेस्ट नहीं हारी टीम इंडिया, कोरोना के बीच देश में पहली बार फैंस को एंट्री

चेन्नई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शनिवार से चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम (चेपक) में शुरू हो रहा है। पहले मैच में हार के कारण टीम इंडिया दबाव में है। लिहाजा प्लेइंग-11 में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। भारत के प्रैक्टिस सेशन और BCCI सूत्रों से जो संकेत मिले हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि टीम इस मुकाबले में भी तीन स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल के अलावा एक रिस्ट स्पिनर को रविचंद्रन अश्विन का साथ देने का मौका मिल सकता है। यह देखने वाली बात होगी कि वह रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव होते हैं या राहुल चाहर।

टीम इंडिया के लिए, राहत की बात यह है कि उसे पिछले 8 साल में घरेलू मैदानों पर लगातार दो टेस्ट मैच में हार नहीं झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर मुसीबत यह है कि आखिरी बार भारतीय टीम को भारत में लगातार दो टेस्ट मैच में हराने का कारनामा इंग्लैंड ने ही किया था। 2012 में इंग्लैंड ने मुंबई और कोलकाता में खेले गए लगातार दो टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी। इंग्लैंड की टीम ने तब सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी।

अक्षर के खिलाफ स्वीप शॉट आसान नहीं

अक्षर पटेल पहले टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम मैनेजमेंट की पसंद थे, लेकिन मुकाबले से ठीक पहले वे चोटिल हो गए और उनकी जगह शाहबाज नदीम को शामिल किया गया। अक्षर की बॉलिंग स्पीड नदीम से अधिक है। इसलिए उनके खिलाफ स्वीप शॉट खेलना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। साथ ही अक्षर लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं।

वॉशिंगटन सुंदर को होना पड़ सकता है बाहर

भारतीय थिंक टैंक का साफ मानना है कि पांच गेंदबाजों में दो ऐसे होने चाहिए, जो बल्ले के साथ भी ठीक-ठाक योगदान कर सकें। इससे टीम की टेल बहुत लंबी नहीं होती है और बैटिंग ऑर्डर में गहराई आती

है। जब अक्षर पहले टेस्ट से बाहर हुए तो बैटिंग एबिलिटी के कारण ही वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह मिली। अगर अक्षर वापस आते हैं तो सुंदर को बाहर होना पड़ सकता है। इस स्थिति में सुंदर की जगह एक रिस्ट स्पिनर को मौका मिलेगा। पांच गेंदबाजों में दो अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ऐसे गेंदबाज होंगे, जो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं।

बुमराह और सिराज में एक को मौका

टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में भी बदलाव कर सकती है। पहले टेस्ट में इशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह खेले थे। बुमराह पहले टेस्ट में खास प्रभावशाली नजर नहीं आए। विशेषज्ञों का मानना है कि बुमराह को अभी और आराम दिया जाना चाहिए। इस स्थिति में दूसरे टेस्ट में बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज का चयन किया जा सकता है। हालांकि, इस बारे में आखिरी फैसला बुमराह से सलाह करने के बाद ही लिया जाएगा।

जोफ्रा आर्चर चोटिल, नहीं खेलेंगे दूसरा टेस्ट

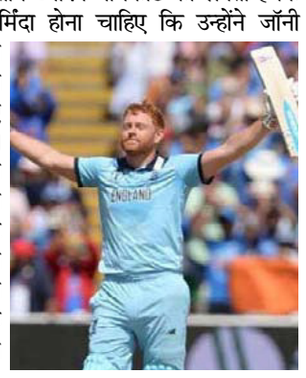

इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर चोटिल होने के कारण दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उन्हें दायीं कोहनी में चोट लगी है और दर्द कम करने के लिए उन्हें इंजेक्शन भी लेना पड़ा है। आर्चर की जगह स्टुअर्ट ब्रॉड को प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है। इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट से जेम्स एंडरसन को आराम देना चाह रही थी लेकिन अब आर्चर की चोट के कारण एंडरसन का खेलना तय माना जा रहा है।

पिच के दो ऑप्शन मौजूद

पहले मैच की पिच को लेकर देश के सबसे दिग्गज क्यूरेटर दलजीत सिंह की तारीफ पाने वाले वी रमेश कुमार ने दूसरे टेस्ट के लिए दो पिचें तैयार की हैं। एक पिच लाल मिट्टी से बनी है। वहीं, दूसरी पिच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से बनी है। एक पिच का मिजाज पहले टेस्ट की पिच जैसा ही हो सकता है। दूसरी पिच को इस लिहाज से तैयार किया गया है कि उस पर पहले दिन से स्पिनरों को मदद मिले। कौन सी पिच पर मैच होगा, यह फैसला भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को लेना है।

संजू सैमसन समेत छह भारतीय खिलाड़ी 2 किलोमीटर रन फिटनेस टेस्ट में हुए फेल, BCCI ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल को और उंचा करने के लिए इस साल से यो-यो टेस्ट के साथ दो किलोमीटर रन फिटनेस टेस्ट का नया नियम बनाया था। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को देखते हुए सीनियर खिलाड़ियों को इस टेस्ट से छूट दी गई थी, लेकिन अब बोर्ड ने पहली बार जूनियर-लेवल के खिलाड़ियों के लिए इस टेस्ट का आयोजन किया। इस टेस्ट में संजू सैमसन, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, सिद्धार्थ कौल, जयदेव उनादकट व ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब खबर ये आ रही

है कि, संजू सैमसन समेत ये छह खिलाड़ी इस टेस्ट में फेल हो गए।

इन खिलाड़ियों के फेल हो जाने के बाद बीसीसीआइ ने एक और मौका देने की बात कही है क्योंकि ये इनके लिए पहला मौका था। अब अगर दूसरे चांस में ये खिलाड़ी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर उनका टीम में चयन खतरे में पड़ सकता है। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि, ये एक नए प्रकार का फिटनेस टेस्ट है ऐसे में उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा और कुछ गैप के बाद इसके लिए नई तारीख निश्चित की जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी दूसरी बार फेल हो जाता है तो इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 और तीन वनडे मैचों के लिए जिस टीम का चयन किया जाएगा उसमें इनका चुनाव नहीं होगा।

आपको बता दें कि, जब पहली बार यो-यो टेस्ट का नियम आया था तब मो. शमी और अंबाती रायुडू जैसे खिलाड़ी इसे पास नहीं कर पाए थे और फिर बाद में उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया और उसे पास करने के बाद ही भारतीय टीम में वापसी कर पाए थे। 2 किलोमीटर टेस्ट में फेल होने वाले खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम संजू सैमसन का है क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं।

बीसीसीआइ के सूत्र ने कहा कि, ये टेस्ट उन खिलाड़ियों का किया गया था जो इंग्लैंड के खिलाफ सिमित प्रारूप के सीरीज के लिए टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं साथ ही वो भविष्य के खिलाड़ी भी हैं। पहले यो-यो टेस्ट आया और अब दो किलोमीटर रन फिटनेस टेस्ट आया है। इस टेस्ट में बैट्समैन, विकेटकीपर व स्पिनर को दो किलोमीटर की दूरी 8 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होती है जबकि तेज गेंदबाज के लिए इसका समय 8 मिनट 15 सेकेंड का रखा गया है। सूत्र ने कहा कि, टीम के कप्तान विराट कोहली व कोच रवि शास्त्री इस टेस्ट को भी यो-यो टेस्ट की तरह सबके लिए अनिवार्य करना चाहते हैं।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर भड़के पूर्व कप्तान, कहा- शर्म आनी चाहिए कि इस खिलाड़ी को नहीं खिलाया

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ज्योफ्री बॉयकॉट को लगता है कि वर्तमान टीम प्रबंधन को शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने जॉनी बेयरस्टो के टेस्ट करियर को कैसे संभाला है, जिन्हें भारत में पहले दो मैचों के लिए आराम दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज बेयरस्टो को इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खिलाया था, लेकिन भारत के खिलाफ उनको वर्कलोड प्रबंधन की वजह से बाहर रखा था।

जॉनी बेयरस्टो भारत में अंतिम दो टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन बॉयकॉट को लगता है कि उन्हें जोस बटलर की जगह दूसरे टेस्ट के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह लेनी चाहिए थी न कि बेन फोक्स को। चेन्नई में पहले टेस्ट मैच के बाद जोस बटलर को आराम दिया गया है और वह दौरे के सीमित ओवरों की सीरीज के बाद स्वदेश लौट आएंगे।

बॉयकॉट ने द टेलिग्राफ से बात करते हुए कहा, ÷इसलिए मैं बटलर को भारत छोड़ते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन यह खराब है कि उनके जाने के बाद बेयरस्टो को दूसरे टेस्ट के लिए जगह नहीं दी जा रही है। यह होना ही है, क्योंकि ईडी स्मिथ (मुख्य चयनकर्ता) बेन फोक्स को देखना चाहते हैं। स्मिथ स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि जॉनी बेयरस्टो एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलें।÷

उन्होंने आगे कहा, उन्होंने (बेयरस्टो) हमेशा कहा है कि वह अपने पिता की तरह एक विकेटकीपर बल्लेबाज बनना चाहते हैं। वह सिर्फ एक विशेषज्ञ बल्लेबाज नहीं बनना चाहते, लेकिन स्मिथ ने यह फैसला किया है और मुझे लगता है कि यह अनुचित है। जॉनी ने फिर से कीपिंग करने के अपने मौके को गंवा दिया और इंग्लैंड को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है। अगर इंग्लैंड को उनको खिलाना है तो फिर उनको मौके देने होंगे।

आईपीएल ऑक्शन 2021

292 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी

श्रीसंत का नाम नहीं; सैयद किरमानी के 31 साल के बेटे को मिली जगह

मुंबई। 18 फरवरी को होने वाली IPL की नीलामी के लिए 292 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन शॉन मार्श, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन और साउथ अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर मोर्ने मोर्कल उन 17 नए नामों में शामिल हैं, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में जगह दी गई है। इन खिलाड़ियों का नाम फ्रेंचाइजीज की रिक्वेस्ट पर डाला गया है।

हैरानी की बात है कि इसमें टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (38) को जगह नहीं दी गई है। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमानी के 31 साल के बेटे को जगह मिली है। सैयद किरमानी 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।

सिर्फ 2 लिस्ट ए मैच खेल सके हैं सादिक किरमानी

सैयद किरमानी के बेटे सादिक किरमानी भी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में वे कर्नाटक के लिए सिर्फ दो लिस्ट ए मैच खेल पाए हैं। उन्होंने अपना आखिरी लिस्ट ए मैच 2015 में खेला था। टी20 में भी उन्होंने अपना आखिरी मैच ढाई साल पहले 2018 में कर्नाटक प्रीमियर लीग में खेला था।

श्रीसंत ने 75 लाख रुपए रखी थी अपनी बेस प्राइस

श्रीसंत ने नीलामी के लिए खुद को रजिस्टर कराया था और अपनी बेस प्राइस 75 लाख रुपए

रखी थी। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने के कारण BCCI ने श्रीसंत पर आजीवन बैन लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आजीवन बैन को खत्म कर दिया था। लेकिन, अब IPL मैनेजमेंट के रुख से लग रहा है कि श्रीसंत के लिए वापसी करना आसान नहीं होने वाला है।

61 खिलाड़ियों पर लग सकती है बोली

IPL के अगले सीजन के लिए 8 फ्रेंचाइजी के पास कुल 61 स्लॉट खाली हैं। इन 61 स्थानों में 22 विदेशी खिलाड़ियों की जगह भी खाली है। इन खिलाड़ियों को 1097 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के पूल में से शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें भारत के 164 और अन्य देशों के 128 खिलाड़ी शामिल हैं।

10 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए

शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों में 10 नाम ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होगी। इनमें भारत के हरभजन सिंह और केदार जाधव भी शामिल हैं। 2 करोड़ बेस प्राइस में अन्य खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ (दोनों ऑस्ट्रेलिया), मोइन अली, सैम बिलिंग्स, लियाम प्लंकेट, जेसन रॉय, मार्क वुड (सभी इंग्लैंड) और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी इन 10 खिलाड़ियों में मौजूद हैं। पहले इस ब्रैकेट में मौजूद दक्षिण अफ्रीका के कोलिन इनग्राम अब इसका हिस्सा नहीं हैं।

कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ शुरू होगी बोली: IPL ने सभी फ्रेंचाइजी को इन्फॉर्म किया है कि नीलामी की शुरुआत 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे से कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ होगी। इनमें सबसे पहले बल्लेबाजों पर बोली लगेगी। इसके बाद ऑलराउंडर, विकेटकीपर, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर का नंबर आएगा। अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली के लिए भी इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। IPL ने यह भी बताया कि 87 खिलाड़ियों पर बोली लगने के बाद नीलामी की तेज प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें सभी अनरिप्रेजेंटेड और अनसोल्ड खिलाड़ियों पर बोली लगेगी।

बायर्न म्यूनिख ने जीता क्लब वर्ल्ड कप

एक साल में छठा खिताब जीता, यह उपलब्धि हासिल करने वाली बार्सिलोना के बाद दूसरी टीम

कतर। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। यह 12 महीने में उनका छठा खिताब रहा। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह इतिहास की दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले स्पेनिश क्लब बार्सिलोना 2009 में यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी बार्सिलोना से ही खेलते हैं। बायर्न ने वर्ल्ड कप के फाइनल में मैक्सिको के क्लब टाइग्रेस UANL को 1-0 से शिकस्त दी। मैच में अकेला गोल बेंजामिन पवर्ड ने 59वें मिनट में किया। मैच में बायर्न के पास सबसे ज्यादा 56फीसदी पजेशन रहा। पास भी इसी टीम ने सबसे ज्यादा 556 किए।

लेवानदोस्की को गोल्डन बॉल ट्रॉफी

बायर्न के स्टार स्ट्राइक रॉबर्ट लेवानदोस्की को गोल्डन बॉल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वे पिछले साल ख्रुद्रम्न प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। साथ ही टाइग्रेस टीम के आंद्रे-पियरे गिग्नाक को सिल्वर बॉल ट्रॉफी के लिए चुना गया। पिछले 8 साल से श्र्म्न चैम्पियंस लीग की विजेता टीम ही वर्ल्ड कप खिताब भी जीत रही है। यह सिलसिला इस बार भी जारी रहा। बायर्न ने पिछले साल ही फाइनल में पेरिस-सेंट जर्मेन को हराकर चैम्पियंस लीग खिताब जीता था। अब वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया है।

जो रूट फिर बाहर:भारत दौरे पर 5 टी-20 मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित

लंदन। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे चल रहे इंग्लैंड ने 12 मार्च से शुरू हो रही 5 टी20 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट को एक बार फिर 16 सदस्यों वाली टीम से बाहर रखा गया है। वहीं, विकेटकीपर के तौर पर जोस बटलर को मौका दिया गया है। बटलर भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट गए हैं। वे अब टी20 सीरीज से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे। पांचों टी20 मुकाबले अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे।

लियाम लिविंगस्टोन को मौका

इंग्लैंड ने 27 साल के ओपनिंग बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को टीम में

शामिल किया है। लिविंगस्टोन साउथ अफ्रीका गई इंग्लिश वनडे टीम का हिस्सा थे। उन्होंने हाल ही समाप्त हुई बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स की ओर से अच्छा परफॉर्म किया था।

मई 2019 के बाद से रूट को मौका नहीं

जो रूट ने लंबे समय से इंग्लैंड की टी20 टीम से बाहर हैं। उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में 5 मई 2019 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। रूट ने अब तक 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 126.30 के स्ट्राइक रेट से 893 रन बनाए हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं।

दोनों टीमों के बीच अब तक हुए हैं 14 मुकाबले

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। इसमें दोनों के हिस्से 7-7 जीत आई है। भारतीय जमीन पर भी भारत और इंग्लैंड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। भारत में अब तक दोनों टीमों के बीच 6 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। इनमें दोनों टीमों को 3-3 मैचों में जीत मिली है।

इंग्लैंड की टी20 टीम

इयोन मोर्गन (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जोस बटलर, सैम करेन, टॉम करेन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, रीस टॉपली और मार्क वुड।

रिजर्व खिलाड़ी: जैक बॉल और मार्क पार्किंसन।

भारत के लिए अच्छी खबर, दूसरे टेस्ट मैच से पहले ही तेज़ गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर बाहर

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले ही इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज़ गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर को चोट लगने के चलते उन्हें टेस्ट से बाहर कर दिया गया है।

बोर्ड ने दी जानकारी

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अपने बयान में कहा कि जोफ्रा आर्चर दायीं को कोहनी के दर्द के कारण भारत के खिलाफ शनिवार से चेन्नई में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। वह इसी स्थान पर पहले टेस्ट के दौरान असहज महसूस कर रहे थे। यह मैच इंग्लैंड ने 227 रन से जीता था।

तीसरे टेस्ट मैच में वापसी

आपको बता दें, जोफ्रा आर्चर ने पहले टेस्ट मैच में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए थे, जिसमें पहली पारी में रोहित शर्मा का विकेट भी शामिल था। ईसीबी ने स्पष्ट किया है की तेज़ गेंदबाज़ को किसी पिछली परेशानी के कारण यह चोट नहीं लगी। बोर्ड ने बताया कि यह मामला किसी पिछली चोट से जुड़ा हुआ नहीं है और उम्मीद है कि उपचार से जल्द सामान्य हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जोफ्रा आर्चर अलग जल्द स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट

मैच में वापसी कर पाएगा।

इस क्रिकेटर ने किया रिप्लेस

जोफ्रा आर्चर के मैच से बाहर होने के बाद जेम्स एंडरसन के साथ अनुभवी स्टुअर्ट ब्रॉड का अंतिम एकादश में चुना जाना तय है। वही पहले टेस्ट में हिस्सा लेने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर भी इंग्लैंड वापस लौट चुके हैं। उनकी जगह बेन फोक्स मैच खेलते नज़र आएंगे। फोक्स के पास पांच टेस्ट मैचों का अनुभव है। आइए जानतें है इंग्लैंड और भारत में कैन कौन से प्लेयर्स मैदान में उतरेंगे।

इंग्लैंड की टीम

जो रूट (कप्तान), ओली पोप, डैनियल लॉरेंस, डॉमनिक सिबले, मोईन अली, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, रॉरी बर्न्स, बेन फोक्स (विकेटकीपर), जेम्स एंडरसन, डॉमनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच और ओली स्टोन।

भारत की टीम

विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, केएल राहुल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर।

विराट कोहली को लेकर विरोधी कप्तान जो रूट ने कहा- दूसरे टेस्ट में उनसे है इस बात की उम्मीद

नई दिल्ली। टीम इंडिया को विराट कोहली की कप्तानी में पहले ही टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने बुरी तरह से हरा दिया था और इसके बाद उनकी कप्तानी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। क्रिकेट फैंस ने भी भारतीय टीम की हार के बाद अपने-अपने तरीके से नाराजगी जाहिर की थी। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार चार टेस्ट मैंच गंवा चुकी है और ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती है कि, वो किस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ अगले तीन मैचों में खुद को साबित कर पाते हैं।

वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले विरोधी टीम के कप्तान जो रूट ने कहा है कि, उन्हें आशा है कि विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच की पहली ही गेंद से हमें सीधी टक्कर देंगे। विराट कोहली ने पहले मैच के लिए जिस टीम का चयन किया था उसे लेकर भी उनकी आलोचना की जा रही है। जो रूट ने कहा कि, मुझे आशा है कि विराट कोहली वापसी करना चाहते हैं और दूसरे टेस्ट मैच की पहली ही गेंद से अपना जवाब देना चाहते हैं। वो कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर अपनी धरती पर अविश्वनीय रिकॉर्ड के साथ गर्व किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। वो इस टेस्ट सीरीज में जल्द से जल्द वापसी करना चाहते हैं। जो रूट ने इंडिया टूडे के हवाले ये बातें कहीं।

जो रूट ने इंग्लैंड की तैयारियों के बारे में कहा कि, हमारी टीम उन चुनौतियों का जवाब देने के पूरी तरह से तैयार है जैसा कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में

किया था। जिस तरह से हमने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट और भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में खेला था उसी तरह से खेलने की फिर से कोशिश करेंगे। हमारे सामने जिस भी तरह की पिच हो जैसी भी कंडीशन हो हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम गेम में मजबूती से बने रहने के लिए पूरी तरह से क्रूर बनने की कोशिश करेंगे। हम जिस तरह से खेलना चाहते हैं उसी तरह से खेलेंगे और ये सबसे अहम है। हमारे लिए सबसे अहम ये है कि, हम अपने गेम प्लान पर पूरी तरह से फोकस करें। दूसरा टेस्ट मैच दोनों देशों के बीच में चेन्नई में खेला जाएगा।